RNI No : MPHIN/2022/82783
कुल पृष्ठ : 52, मूल्य : 50 रुपए
वर्ष 03, अंक 8 मासिक पत्रिका
25 अगस्त 2024

हमारा देश हमारा अभिमान

हर-हर महादेव

मौत बांटते...

असुरक्षित कोचिंग सेंटर, पीजी और हॉस्टल

हमारा देश
हमारा अभिमान

हर-हर महादेव

स्वतंत्रता दिवस
की
हार्दिक शुभकामनाएं

शुभकामनाकर्ता :

हमारा देश हमारा अभिमान मासिक पत्रिका एवं समस्त परिवार...

हमारा देश
हमाराअभिमान

25 अगस्त 2024

वरिष्ठ संरक्षक मंडल

- अनन्त श्री विभूषित श्रीमद जगद्गुरु श्री राम स्वरूपचार्य जी महाराज कामदगिरि पीठाधीश्वर चित्रकूट धाम
- श्री महामंडलेश्वर रामप्रिय दास
- श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर अनिरुद वन जी, श्री धूमेस्वर धाम
- श्री डॉ. श्रीमन नारायण मिश्रा
- डॉ. श्रीमती शालिनी कौशिक
- श्री नागेंद्रनाथ सुरेंद्र नाथ चौबे

संरक्षक मंडल

- श्री लोकेश चतुर्वेदी
- श्री डॉ. दिनेश उपाध्याय
- श्री अरविंद जैन
- श्री प्रदीप कुमार शर्मा
- श्री शिवदयाल धाकड़
- श्री अरुण कांत शर्मा
- श्री महेश पुरोहित
- श्री विनोद भारद्वाज, अधिवक्ता ग्वालियर हाईकोर्ट,
- श्री मनोज भारद्वाज
- श्री अनिल जैन
- श्री निर्मल वासवानी
- श्री विद्याभूषण शर्मा
- श्रीमती अर्चना बाजपेयी
- एडवोकेट श्रीमती रिचा पांडेय (सुप्रीम कोर्ट)
- श्री के.एल.दलवानी
- श्री राकेश कुमार सगर
- श्री जयराज कुबेर
- श्री अभिनव पल्लव
- श्री बृजेश श्रीवास्तव
- श्री दीपक कुमार शुक्ला
- श्रीमति निवेदिता गुप्ता
- श्री विनोद कुमार बांगडे
- श्री विनायक शर्मा
- कमांडो कमल किशोर (पूर्व सांसद)
- श्री के. कान्याल

संपादक : मनोज चतुर्वेदी

पंकज दीक्षित
प्रमुख परामर्शदाता

विशेष संवाददाता
- रवि परिहार • रविकांत शर्मा

कानूनी सलाहकार
- एडवोकेट अनिल शुक्ला शासकीय अधिवक्ता, ग्वालियर हाईकोर्ट
- एडवोकेट एस.के. पाठक, ग्वालियर
- दीपेंद्र कुमार पाण्डेय, एडवोकेट, उच्च न्यायालय

ब्यूरो : अविनाश (उज्जैन संभाग)

छिंदवाड़ा ब्यूरो : जितेंद्र चौरे

मुम्बई ब्यूरो (महाराष्ट्र)
सचिंदर शर्मा (फ़िल्म डायरेक्टर)

सलाहकार

- डॉ सुनील शर्मा, नेत्र रोग विशेषज्ञ
- श्री डॉ. मुकेश चतुर्वेदी
- डॉ. दिनेश प्रसाद (हड्डी रोग सर्जन)
- श्री अनिल दुबे
- श्री विकास चतुर्वेदी
- श्री सुरेश शर्मा
- श्री नारायणदास गुप्ता
- श्री पीयूष श्रीवास्तव
- पंडित श्री चंद्रशेखर शास्त्री
- श्री बृज मोहन आर्य
- श्री विवेक शर्मा
- श्री अशोक कुमार वर्मा
- श्री आनंद कुमार
- श्रीमती रितु मुदगल
- श्री कुंज बिहारी शर्मा
- सुश्री पूजा मावई
- श्री संदीप कुमार पांडेय
- श्री मनोज सिंह
- प्रदीप यादव
- निरंजन शर्मा
- विनीत गोयल
- डॉ. सुधीर राजौरिया, हड्डी रोग विशेषज्ञ
- आशीष त्रिवेदी
- डॉक्टर अशोक राजौरिया
- हेमाटोलाजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट
- डॉक्टर कमल कटारिया
- यशवंत गोयल
- दीपक भार्गव
- अमित जैन इंदौर
- सुरजीत परमार
- संजू जादौन
- डॉक्टर हिमांशु डेंटिस्ट
- रागिनी चतुर्वेदी
- प्रवेंद्र चतुर्वेदी
- प्रखर सिंह

ब्यूरो राजस्थान
सुभाष सोरल (फ़िल्म निर्माता) कोटा

ब्रजेश जैन साक्षात्कार व्यवस्थापक और विज्ञापन संवाददाता इंदौर

संवाददाता : संदीप पाटिल, इंदौर

मार्केटिंग प्रमुख : शैलेन्द्र जैन

मार्केटिंग मैनेजर
- सुनील • हरशूल

डिजाइन : मनोज पंवार

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक मनोज कुमार चतुर्वेदी द्वारा कंचन ऑफसेट डी-1/63, सेक्टर-4, विनय नगर ग्वालियर- फोन नं. 0751-2481433, (म. प्र.) से मुद्रित एवं शिव कॉलोनी गली नं. 4 , रेलवे स्टेशन के पीछे, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर, (मध्यप्रदेश) प्रकाशित। संपादक-मनोज कुमार चतुर्वेदी ।
(सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र ग्वालियर रहेगा।)

विवरणिका

संपादकीय	.....	02
शुभाशीष	.....	03
कवर स्टोरी	.....	04-05
देश	.....	06
विदेश	.....	07
देश	.....	08
देश	.....	18-19
इन्दौर	.....	24-25
देश	.....	26
विदेश	.....	27
देश	.....	28-29
मध्यप्रदेश	.....	30
देश	.....	31
आर्थिक	.....	32
मध्यप्रदेश	.....	33
देश-विदेश	.....	34
दुग्ध उत्पादन	.....	36
कृषि	.....	37
कृषि	.....	38
देश	.....	39
देश	.....	40-41
प्रदेश	.....	40-41
स्वास्थ्य	.....	44
धर्म	.....	45
जीवनशैली	.....	46
खेल	.....	47

48

'स्त्री 2' के बाद नागिन की भूमिका में नजर आएंगी श्रद्धा

संपादकीय

विकसित भारत को गढ़ने के संकल्पों का उद्बोधन...

प्रधानमंत्री मोदी के सम्बोधन को वास्तविकता की रोशनी में नये भारत-सशक्त भारत-विकसित भारत के रुप में देखा जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता को जरुरी बताने के साथ-साथ प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक आपदा से लेकर रिफार्म्स तक, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों से लेकर गवर्नेस मॉडल, रोजगार, व्यापार, रक्षा, चिकित्सा समेत कई विषयों की चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लालकिले की प्राचीर से 78वें स्वतंत्रता दिवस का अब तक का सबसे लम्बा 98 मिनट का 11वां राष्ट्रीय उद्बोधन एक विशाल एवं विराट इतिहास को समेटे हुए नये भारत के नये संकल्पों की बानगी है। जो आजादी के अमृतकाल को अमृतमय बनाने के लिये लोगों को ऊंचे सपने देखने, बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने वर्तमान की वैश्विक एवं राजनैतिक चुनौतियों को भविष्य की अपनी दृष्टि पर हावी नहीं होने दिया। यह उद्बोधन भारत की भावी दशा-दिशा रेखांकित करते हुए उसे विश्व गुरु बनाने एवं दुनिया की आर्थिक महाताकत बनाने का आह्वान है। यह शांति का उजाला, समृद्धि का राजपथ, उजाले का भरोसा एवं महाशक्ति बनने का संकल्प है। लालकिले से जब देश का प्रधानमंत्री बोलता है तो वह भारत के महान लोकतंत्र की उस आत्मा को साकार करता है जो इस देश के 140 करोड़ देशवासियों के भीतर बसती है। प्रधानमंत्री मोदी के सम्बोधन को वास्तविकता की रोशनी में नये भारत-सशक्त भारत-विकसित भारत के रुप में देखा जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता को जरुरी बताने के साथ-साथ प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक आपदा से लेकर रिफार्म्स तक, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों से लेकर गवर्नेस मॉडल, रोजगार, व्यापार, रक्षा, चिकित्सा समेत कई विषयों की चर्चा की। उन्होंने न्यायिक सुधारों पर आगे बढ़ने का भी संकेत दिया। इसके साथ ही वह विपक्ष को निशाना बनाने से नहीं चूके और सरकार का एजेंडा उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। निश्चित ही अब तक हुए लालकिले की प्राचीर के उद्बोधनों में सर्वाधिक प्रेरक, संकल्पमय एवं विकसित भारत की इबारत लिखने वाला यह उद्बोधन रहा।

मनोज चतुर्वेदी
संपादक

शुभाशीष

हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए बढ़ावा देना होगा

कांग्रेस और इंडी गठबंधन जिसकी अधिकांश पार्टियाँ जाति आधारित हैं अपने मतदाताओं को जोड़े रखने के लिए आरक्षण के बहाने जाति का कार्ड खेल रही हैं। कांग्रेस और भी नीचे जाकर इस जाति कार्ड को संविधान की रक्षा का नाम दे रही है और एक भ्रमजाल फैला रही है। अट्ठारवीं लोकसभा के लिए भारत की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सराकर चलाने का निर्णय तो दिया किन्तु साथ ही विपक्ष भी अपनी सीटें बढ़ाने में सफल रहा। बढ़ी हुई सीटों के साथ आक्रामक विपक्ष यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि जनता ने उन्हें संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए चुना है जबकि वास्तविकता ये है कि उनकी बढ़ी हुई सीटें एक वर्ग के उनके झूठ में फँस जाने के कारण आई हैं ।विपक्ष को अपनी बढ़ी हुई सीटों के कारण यह आत्मविश्वास मिल गया है कि अब आरक्षण और जाति के आधार पर भाजपा, संघ व हिंदुत्व को कमजोर करके सत्ता प्राप्त की जा सकती है। विपक्ष के लिए जातिगत मुद्दे सत्ता प्राप्ति का मार्ग हो सकते हैं किन्तु हिन्दू समाज के अस्तित्व के लिए इन मुद्दों का उभार एक बड़े संकट का आरम्भ है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन जिसकी अधिकांश पार्टियाँ जाति आधारित हैं अपने मतदाताओं को जोड़े रखने के लिए आरक्षण के बहाने जाति का कार्ड खेल रही हैं। कांग्रेस और भी नीचे जाकर इस जाति कार्ड को संविधान की रक्षा का नाम दे रही है और एक भ्रमजाल फैला रही है। लोकसभा चुनावों से पहले किया गया झूठ का प्रयोग अब और व्यापक हो रहा है, राहुल गांधी जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं उससे यह प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस अब पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग का विस्तरित रुप ले चुकी है। विगत दिनों ऐसी कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं जिन पर कांग्रेस व इंडी गठबंधन के नेताओं का रुख जाती और आरक्षण के नाम पर देश को अराजकता में झोंकने वाला रहा है। इंडी गठबंधन के विभिन्न दलों के नेता तथा हर बात पर जाति पूछ रहे हैं और हर चर्चा को उसी धारा में मोड़ने का विकृत प्रयास कर रहे हैं। राहुल गाँधी द्वारा संसद के बजट सत्र में, बजट टीम का चित्र दिखाकर उसमें अधिकारियों की जाति पूछना एक ऐसा ही निंदनीय और घृणित प्रयास था ।

डॉ. श्रीमन नारायण मिश्रा
संरक्षक

मौत बांटते...

असुरक्षित कोचिंग सेंटर, पीजी और हॉस्टल

राजधानी के ओल्ड राजेन्द्र नगर के कोचिंग सैंटर में हुए हादसे में तीन छात्रों नेविन डोल्विन, तान्या सोनी और श्रेया यादव की दुखद मौत ने अनेक सवालों को खड़ा किया है। केरल का रहने वाला नेविन आईएएस की तैयारी कर रहा था और वह जेएनयू से पीएचडी भी कर रहा था।

दिल्ली में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराने वाले एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से तीन छात्रों की मौत-हादसे ने समूचे राष्ट्र को दुःखी एवं आहत किया है, यह हादसा नहीं, बल्कि मानव जनित त्रासदी है, लापरवाही एवं लोभ की पराकाष्ठा है। इस त्रासदी की जड़ में है घोर दोषग्रस्त कोचिंग प्रणाली और व्यवस्था की जड़ों में समा गया बेलगाम भ्रष्टाचार। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि कोचिंग संस्थान के दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के उन कर्मचारियों और अधिकारियों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया जो सब कुछ जानते-बूझते हुए इस संस्थान को बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की सुविधा प्रदान किए हुए थे। इस दुःखद एवं पीड़ादायक घटना ने एक बार फिर यही साबित किया है कि निर्माण कार्यों में फैले व्यापक भ्रष्टाचार और शासन तंत्र में बैठे लोगों की मिलीभगत के बीच ईमानदारी, नैतिकता, जिम्मेदारी या संवेदनशीलता जैसी बातों की जगह नहीं है। जिसकी कीमत निर्दोषों को अपनी जान गंवा का चुकानी पड़ रही है। निश्चित ही

देशभर में कुकुरमुत्तों की तरह उग आए कोचिंग सैंटर डैथ सैंटर बन चुके हैं। कोचिंग सैंटरों का कारोबार शासन के दिशा-निर्देशों की धज्जियां उड़ाकर चल रहे हैं। छात्रों को सुनहरी भविष्य का सपना दिखा कर मौत बांटी जा रही है। आजादी के अमृत-काल में पहुंचने के बाद भी भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बेईमानी हमारी व्यवस्था में तीव्रता से व्याप्त है, अनेक हादसों एवं जानमाल की हानि के बावजूद भ्रष्ट हो चुकी मोटी चमड़ी पर कोई असर नहीं होता। प्रश्न है कि सैंटर के मालिक को तो गिरफ्तार कर लिया लेकिन ऐसी घटनाओं के दोषी अधिकारी क्यों नहीं गिरफ्तार होते?

राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेन्द्र नगर के कोचिंग सैंटर में हुए हादसे में तीन छात्रों नेविन डोल्विन, तान्या सोनी और श्रेया यादव की दुखद मौत ने अनेक सवालों को खड़ा किया है। केरल का रहने वाला नेविन आईएएस की तैयारी कर रहा था और वह जेएनयू से पीएचडी भी कर रहा था। उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव ने अभी एक महीना पहले ही इस कोचिंग सैंटर में दाखिला लिया था। कोचिंग सैंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी जहां 150 छात्रों के बैठने की व्यवस्था थी। हादसे के वक्त 35 छात्र मौजूद थे। चंद मिनटों में ही बेसमेंट में पानी भर गया। सिर्फ इसी सैंटर में नहीं, बल्कि लगभग सभी शैक्षणिक कोचिंग सैंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई गई है। जिसके गेट बायोमेट्रिक आईडी से खुलते हैं, जैसे ही बारिश होती है, बिजली चली जाती है, उसके बाद बेसमेंट से निकलना बिना बायोमैट्रिक आईडेंटिफिकेशन के मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में हादसे और मौत की संभावना बढ़ जाती है। ओल्ड राजेंद्र नगर के न सिर्फ कोचिंग सैंटर बल्कि पीजी और हॉस्टल की असुरक्षित हालत भी मौत लिये किसी भी क्षण बड़े हादसे की संभावना के साथ खड़ी है। जहां इस कदर अवैध निर्माण है कि कभी भी दूसरा या दोबारा हादसा हो सकता है। इसलिये ऐसे हादसों की जांच से काम नहीं चलने वाला। विडम्बनापूर्ण है ऐसे जलभराव एवं आगजनी के हादसों से सबक नहीं लिया जाता। यह प्रवृत्ति दुर्भाग्यपूर्ण है। विडम्बना देखिये कि ऐसे भ्रष्ट शिखरों को बचाने के लिये सरकार कितने सारे झूठ का सहारा लेती है। राजधानी में रह-रह कर एक के बाद एक हो रहे हादसों के बावजूद दिल्ली-सरकार की नींद नहीं खुल रही है। हाल ही में गुजरात के राजकोट में एक एम्यूजमेंट पार्क के अंदर गेमिंग जोन में लगी आग की लपटें हो या राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बच्चों के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आग लगना और अब कोचिंग सैंटर में तीन होनहार एवं देश के भविष्य बच्चों का दर्दनाक तरीके से डूबकर मर जाना-निश्चित रूप से ये हादसे प्रशासनिक लापरवाही की उपज हैं, यही कारण है कि सिस्टम में खामियों और ऐसी आपदाओं को रोकने में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की निंदा भी व्यापक स्तर की जा रही है। यह याद रखने योग्य है कि नियमित अंतराल पर मानवीय जिम्मेदारी वाले पहलू की अनदेखी से ऐसी गंभीर घटनाएं होने के बावजूद अधिकारियों की उदासीनता और लापरवाही कम होती नहीं दिख रही है। इन त्रासद हादसों ने कितने ही परिवारों के घर के चिराग बुझा दिए। परिवार वालों ने और छात्रों ने स्वर्णिम भविष्य के सपने संजो कर और लाखों की फीस देकर कोचिंग शुरू की होगी लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्हें इस तरह मौत मिलेगी। छात्रों की मौत को महज हादसा नहीं माना जा सकता, यह एक तरह से निर्मम हत्या है और हत्यारा है हमारा सिस्टम। हादसे से आक्रोशित छात्रों का कहना है कि वे 10-12 दिन से दिल्ली नगर निगम से कह रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम की सफाई कारवाई जाए लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हादसे तभी होते हैं जब नियमों और कानूनों को ताक पर रखा जाता है। तंत्र की काहिली और आपराधिक लापरवाही के चलते ऐसे हादसे होते हैं जिनमें भ्रष्टाचार पसरा होता है, जब अफसरशाह लापरवाही करते हैं, जब स्वार्थ एवं धनलोलुपता में मूल्य बौने हो जाते हैं और नियमों और कायदे-कानूनों का उल्लंघन होता है। जलभराव क्यों और कैसे हुआ, यह तो जांच का विषय है ही लेकिन इन शैक्षणिक एवं व्यावसायिक इकाइयों को उसके मालिकों ने मौत का कुआं बना रखा था। आखिर क्या वजह है कि जहां दुर्घटनाओं की ज्यादा संभावनाएं होती हैं, वही सारी व्यवस्थाएं फेल दिखाई देती है? सारे कानून कायदों का वहीं पर स्याह हनन होता है। हर दुर्घटना में गलती भ्रष्ट आदमी यानी अधिकारी एवं व्यवसायी की ही होती है, लेकिन दुर्घटना होने के बाद ही उन पर कार्रवाई क्यों होती है? सरकार पहले क्यों नहीं जागती?

वैसे तो बेसमेंट में कोचिंग सैन्टर या लाइब्रेरी चलाना गैर-कानूनी है, इस घटना के सन्दर्भ जब बेसमेंट में स्टोर या पार्किंग की अनुमति दी गई थी तो वहां लाइब्रेरी कैसे चलने लगी? स्पष्ट है कि कोचिंग संचालकों और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसा हो रहा होगा। जलभराव के कारण पानी जब बेसमेंट में घुसा तब लाइब्रेरी में 30-35 छात्र थे। यह तो गनीमत रही कि तीन अभागे छात्रों को छोड़कर बाकी सब जैसे-तैसे निकल आए। इस इलाके में बरसात में हर समय जलभराव होता है, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली। इसका कोई विशेष औचित्य नहीं कि एमसीडी ने एक जांच समिति गठित करने की बात कही है। जांच के नाम पर लीपापोती होने की ही आशंका अधिक है। दिल्ली की घटना इसकी परिचायक है कि जिन पर भी शहरी ढांचे की देखरेख करने और उसे संवारने की जिम्मेदारी है, वे अपना काम सही से करने के लिए तैयार नहीं। यही कारण है कि देश की राजधानी के साथ-साथ अन्य महानगरों का भी शहरी ढांचा बुरी तरह चरमरा गया है।

बात हम नया भारत एवं विकसित भारत की करते हैं, लेकिन हमारी व्यवस्थाएं अभी वैसी नहीं बनी है और हम अनियंत्रित एवं असुरक्षित विकास करते जा रहे हैं। मुंबई हो, दिल्ली हो, चेन्नई या बेंगलुरु या ऐसे ही अन्य बड़े शहर हर कहीं अनियोजित विकास और शहरी निर्माण संबंधी नियम-कानूनों के खुले उल्लंघन के चलते आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। स्थिति यह है कि सरकारी भवनों तक में सुरक्षा के उपायों की अनदेखी होती है। दिल्ली के इनकम टैक्स भवन में आग से एक अधिकारी की जान हाल में गयी। कहने को तो अपने देश में हर तरह के नियम-कानून हैं, लेकिन वे कागजों पर ही अधिक हैं या निर्दोषों को परेशानी करने के लिये है। औसत जनप्रतिनिधि और अधिकारी-कर्मचारी पैसे बनाने के फेर में रहते हैं और अनियोजित विकास को रोकने के बजाय उसे बढ़ावा देने का काम करते हैं। सब चलता है वाली प्रवृत्ति इस तरह अपनी जड़ें जमा चुकी है कि व्यवस्था की परवाह करना ही छोड़ दिया गया है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि शहरी विकास के बड़े-बड़े दावे करने और उन्हें संवारने की तमाम योजनाएं बनाने के बावजूद देश के शहर दुर्दशाग्रस्त एवं असुरक्षित हैं। हर हादसे पर सियासत होती है लेकिन कोचिंग सैंटर माफिया इतना ताकवर है कि उसके आगे कोई कुछ नहीं बोलता। ऐसा क्यों है यह सब जानते हैं।

नकारात्मक राजनीति की पीठ पर सवार है विपक्ष

राहुल गांधी संसद में खड़े होकर जो मन में आता है, बोलते हैं। उनके भाषण का कोई सिरा आपस में जुड़ता नहीं है। असल में वो रटी रटाई स्क्रिप्ट को सदन में दोहराते हैं। वो सरकार पर निशाना साधने और उसकी साख को गिराने के एजेंडे को हर दिन आगे बढ़ाते हैं।

एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जितनी जरूरत एक सशक्त सरकार की होती है, उतना ही सशक्त विपक्ष भी जरूरी होता है। विपक्ष लोकतंत्र के वास्तविक सार के संरक्षण और लोगों की आकांक्षाओं व अपेक्षाओं के प्रकटीकरण में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किंतु, वर्तमान में भारत का विपक्ष झूठ और दुष्प्रचार की राजनीति में गले तक डूबा दिखाई देता है।

एक जीवंत लोकतंत्र में विपक्ष एक निगरानीकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करता है। यह विभिन्न विचारों को व्यक्त करने, समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने और सरकार को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने में सहायक होता है। एक दशक तक लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद रिक्त रहा, क्योंकि सदन में किसी भी पार्टी के पास सदन की कुल सदस्य संख्या के दसवें हिस्से के बराबर सदस्य नहीं थे, जो अब रायबरेली के सांसद राहुल गांधी द्वारा भरा गया है। लेकिन राहुल गांधी विपक्ष के नेता संसदीय सीमाओं, अनुशासन, परंपराओं और कर्तव्यों की लक्ष्मण रेखा प्रतिदिन लांघ रहे हैं। राहुल गांधी संसद में खड़े होकर जो मन में आता है, बोलते हैं। उनके भाषण का कोई सिरा आपस में जुड़ता नहीं है। असल में वो रटी रटाई स्क्रिप्ट को सदन में दोहराते हैं। वो सरकार पर निशाना साधने और उसकी साख को गिराने के एजेंडे को हर दिन आगे बढ़ाते हैं।

चुनाव नतीजों के बाद से ही राहुल गांधी के संसद में दिये गये भाषणों और मीडिया के सामने की गयी बयानबाजी का विश्लेषण करें तो वो सीधे तौर पर देश के हर तबके और वर्ग में असंतोष पैदा करने में जुटे हैं। वो मोदी सरकार की साख पर बट्टा लगाने के मिशन में जुटे हैं। विपक्ष के नेता और विपक्ष की भूमिका के इतर वो हर वो काम कर रहे हैं, जो विशुद्ध तौर पर राजनीति का हिस्सा है।

संसदीय व्यवस्था में विपक्ष की भूमिका की बात करें तो विपक्ष सरकार की नीतियों और कार्यों की जांच करता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। उदाहरण के लिए, भारत में 2जी स्पेक्ट्रम मामले में विपक्ष द्वारा निभाई गई भूमिका ने भ्रष्टाचार और शासन के मुद्दों को उजागर किया।

विपक्ष नीतिगत मामलों पर वैकल्पिक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। 2013 में विपक्ष के रूप में भाजपा ने तत्कालीन यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों की प्रभावी ढंग से आलोचना की, जिससे उसे महत्वपूर्ण चुनावी लाभ हुआ। वहीं विपक्ष विविध और अल्पसंख्यक विचारों का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे बहुलवादी समाज सुनिश्चित होता है। डीएमके और एआईटीसी जैसी क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन सबके अलावा विपक्ष विधायी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे अक्सर कानूनों में सुधार होता है। मौजूदा सरकार के तहत जीएसटी विधेयक में विपक्ष द्वारा सुझाए गए संशोधन इसका एक उदाहरण हैं।

1960 के दशक के आरंभ से भूमि सुधार, औद्योगिक मजदूर वर्ग के अधिकार, बेरोजगारी, खाद्यान्न एवं उनका वितरण, जातीय मांगों और भाषाई अधिकारों जैसे विभिन्न मुद्दों पर पूरे भारत में शक्तिशाली आंदोलनों की शुरुआत हुई। तत्कालीन विपक्ष ने स्वयं को इन सामाजिक आंदोलनों से उल्लेखनीय रूप से संलग्न किया था। इतिहास में संसदीय विपक्ष ने भारत के संसदीय लोकतंत्र को रचनात्मकता और सकारात्मकता प्रदान की थी।

वहीं इस बात में दो राय नहीं है कि कमजोर विपक्ष एक कमजोर या गैर-उत्तरदायी सरकार से कहीं अधिक खतरनाक होता है। और एक गैर-उत्तरदायी, अनुशासहीन और संसदीय परंपराओं को न मानने वाला विपक्ष देश को तबाही की रास्ते पर ले जाता है।

4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही विपक्ष ने इंडी गठबंधन के बैनर तले मोदी सरकार को हर छोटे—बड़े मुद्दे पर घेर रहा है। खासकर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस संसदीय नियमों, लोकतंत्र की मर्यादाओं और परंपराओं को भूलकर लगातार तीन लोकसभा चुनाव में मिली हार की खीझ उतारती दिख रही है।

पिछले तीन आम चुनाव में ये तो साबित हो चुका है कि सीधी लड़ाई में विपक्ष मोदी को शिकस्त देने में सक्षम नहीं है। विपक्ष के झूठ, दुष्प्रचार और गलत बयानबाजी के बावजूद देश के हर वर्ग का विश्वास मोदी के प्रति कायम है। ऐसे में इंडी गठबंधन ने झूठ, दुष्प्रचार और विवादित मुद्दे उछालने की रणनीति पर काम करना शुरू कर रखा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने दुष्प्रचार और झूठ का सहारा लिया है। मोदी तीसरी बार सत्ता में आएंगे तो संविधान बदल देंगे। भोली भाली जनता विपक्ष के दुष्प्रचार के दुष्चक्र में फंसी भी। इस चुनाव में विपक्ष की सीटें 2014 और 2019 के चुनाव की तुलना में बढ़ोत्तरी हुई। विपक्ष के झूठ और दुष्प्रचार के बावजूद मोदी के नेतृत्व में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में सबसे ज्यादा 240 सीटें डाली। जमीनी सच्चाई यह है कि तीसरी बार कांग्रेस विपक्ष में बैठने को मजबूर है। देश की जनता ने उसे सत्ता के लायक नहीं समझा। इस चुनाव में झूठ, षडयंत्र, दुष्प्रचार और पूरी ताकत लगाने के बावजूद विपक्ष सत्ता के करीब नहीं पहुंच पाया। लगातार तीन चुनाव में हार की खीझ, झुंझलाहट, हताशा और निराशा विपक्ष के नेताओं की बयानबाजी में साफ तौर पर झलकती है।

विशेषकर गांधी की गतिविधियां, भाषण और बयानबाजी से ऐसा प्रतीत होता है कि वो देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। राहुल गांधी कभी अग्निवीर और नीट परीक्षा की आड़ में युवाओं को, कभी किसानों को, कभी अल्पसंख्यक समुदायों को, कभी सरकारी कर्मचारियों को, कभी दलित और आदिवासियों के मन में सरकार, संवैधानिक संस्थाओं और व्यवस्था के प्रति रोष, असंतोष और घृणा भरने का काम कर रहे हैं। वो तो देश की जनता इतनी परिपक्व और समझदार है कि वो इनके कुत्सित इरादों ओर नीयत को समझती है। अगर जनता की समझदारी में थोड़ी भी कमी या अपरिपक्वता होती तो चार जून के बाद से अब तक देश में हिंसा और सांप्रदायिक तनाव की कई घटनाएं घट गयी होती। देश में अशांति, असुरक्षा और भय का वातावरण बन गया होता। देश की समझदार और परिपक्व जनता इस समझदारी, धैर्य और अनुशासन के लिये बधाई की पात्र है। राजनीतिक दल अपनी राजनीति चमकाने और आगे बढ़ाने के लिये विरोधी दल की आलोचना करते हैं। ये आम बात है। लेकिन विरोध नीतियों, नीयत और निर्णयों पर होना चाहिए।

क्या भारत को वापस मिलेगा कोहिनूर...

भारत-अमेरिका में हुए समझौते से निकल सकती है राह...

26 जुलाई को दिल्ली और न्यूयॉर्क के बीच हुए एक समझौते में यह तय किया गया है कि (किसी भी देश की गुलामी के दौरान लूटी गई या तस्करी के माध्यम से किसी दूसरे देश को ले जाई गई) पुरातात्विक महत्त्व की कलात्मक वस्तुओं को उसके मूल देशों को वापस लौटाने का प्रयास किया जाएगा। इस समझौते को 'कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट' नाम दिया गया है। देश की गुलामी के दौरान पुरातात्विक महत्त्व की अनेक मूर्तियों, कलात्मक वस्तुओं या रत्न-आभूषणों को अंग्रेजों के द्वारा लूटा गया था। इसके पहले भी अनेक अन्य आक्रमणकारियों ने भारत पर समय-समय पर आक्रमण किया और यहां की बहुमूल्य वस्तुओं को लूटकर अपने साथ ले गए। इन लूटी हुई वस्तुओं में कोहिनूर हीरा भी शामिल है जो इस समय लंदन के ज्वेल हाउस में है। लंबे समय से करोड़ों भारतीयों की इच्छा रही है कि यह कोहिनूर हीरा अब देश में वापस आना चाहिए, लेकिन ब्रिटेन ने अब तक ऐसा कोई रुख नहीं दिखाया है जिससे इस बेशकीमती हीरे के भारत वापसी का रास्ता तैयार हो सके। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच शुक्रवार को हुए एक समझौते के बाद इसकी देश वापसी का रास्ता निकल सकता है।

दरअसल, शुक्रवार 26 जुलाई को दिल्ली और न्यूयॉर्क के बीच हुए एक समझौते में यह तय किया गया है कि (किसी भी देश की गुलामी के दौरान लूटी गई या तस्करी के माध्यम से किसी दूसरे देश को ले जाई गई) पुरातात्विक महत्त्व की कलात्मक वस्तुओं को उसके मूल देशों को वापस लौटाने का प्रयास किया जाएगा। इस समझौते को 'कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट' नाम दिया गया है। इसके लिए भारत और अमेरिका मिलजुलकर प्रयास करेंगे। शुरुआती दौर में यह समझौता भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, लेकिन शीघ्र ही दुनिया के अन्य देशों को भी इससे जोड़ा जाएगा। इस कार्य की सफलता के लिए विभिन्न देशों की एजेंसियों को एक मंच पर लाने और उन्हें इसके लिए सहमत करने की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है। लेकिन इतना स्पष्ट हो गया है कि इस समझौते के बाद पुरातात्विक महत्व की कलात्मक वस्तुओं, मूर्तियों या रत्न-आभूषणों को उनके मूल देश को वापस भेजे जाने का रास्ता तैयार हो सकता है। पुरातात्विक मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ब्रिटेन और भारत के बीच इस मुद्दे पर सहमति बनी तो कोहिनूर के दिल्ली आने का रास्ता बहु तैयार हो सकता है। फिलहाल, यह ब्रिटेन में है।

केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को भारत मंडपम में आयोजित हो रहे 'द हाट ऑफ आर्ट' की तीन दिवसीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान शेखावत ने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच हुए इस समझौते का लाभ केवल हमारे देश को ही नहीं होगा, बल्कि दुनिया के अन्य देशों को भी इसमें शामिल करते हुए पुरातात्विक महत्त्व की वस्तुओं को उनके मूल देशों को वापस करने का प्रयास किया जाएगा। इससे दुनिया के विभिन्न देशों को अपनी विरासत की मूल वस्तुओं को सहेजने का गौरव प्राप्त हो सकेगा।

शेखावत ने बताया कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के आने के पहले केवल 13 पुरातात्विक महत्त्व की वस्तुओं को भारत वापस लाने में सफलता मिली थी, लेकिन 2014 में वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद से लेकर अब तक के दस वर्षों में 357 पुरातात्विक वस्तुओं को दुनिया के अनेक देशों से भारत वापस लाने में सफलता मिली है।

दिल्ली में चल रही विश्व धरोहर समिति की बैठक में भी दुनिया के देशों के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि पुरातात्विक महत्त्व की वस्तुओं को उनके मूल देशों को वापस लौटाया जाए। विश्व धरोहर समिति ने 'मोन्यूमेंट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इंपोर्टेंस' के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। इससे दुनिया के देशों को अपनी विरासत और गौरव की वस्तुओं को वापस लाने में मदद मिल सकती है।

माता अन्नपूर्णा की मूर्ति आई वापस...

दुनिया के दूसरे देशों से भारत में जिन मूर्तियों या कलात्मक वस्तुओं को वापस लाने में सफलता मिली है, उनमें माता अन्नपूर्णा की मूर्ति भी शामिल है। 18वीं शताब्दी की इस मूर्ति को वाराणसी से चुरा लिया गया था, लेकिन केंद्र सरकार के प्रयासों के बाद कनाडा ने इसे भारत को वापस सौंप दिया। भारत लाने के बाद इसे पूरे विधि-विधान से वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में स्थापित कर दिया गया। अभी हाल ही में शिवाजी महाराज के बघनख को स्वदेश वापस लाने में सफलता मिली है। टीपू सुल्तान से जुड़ी कई ऐतिहासिक वस्तुओं को भी भारत वापस लाया जा चुका है। इसी प्रकार की अन्य अनेक वस्तुएं हैं जिसे लोग वापस लाना चाहते हैं। कोहिनूर हीरा भी इन्हीं में शामिल है।

मा. नरोत्तम मिश्रा, पूर्व गृहमंत्री
बंटी गौतम
शुकर्ण मिश्रा
विवेक मिश्रा
सिद्धू गौतम
15 August
स्वतंत्रता दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं
निशांत भार्गव

समस्त प्रदेश एवं देशवासियों को
15
AUGUST
स्वतंत्रता दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं
शुभकामनाएं कर्ता : आनंद कुमार, एसआई थाटीपुर

श्री ओम प्रकाश सखलेचा

पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक

15 अगस्त

स्वतंत्रता दिवस की

हार्दिक शुभकामनाएं...

शुभकामनाएं कर्ता : रामेश्वर सिंह, एसपी ईओडब्ल्यू, इन्दौर

शुभकामनाएं कर्ता : सुरेश राजे डबरा विधायक (कांग्रेस)

शुभकामनाएं कर्ता : जयती सिंह, सीईओ, जिला पंचायत, उज्जैन

शुभकामनाएं कर्ता : डॉक्टर शालिनी कौशिक, वरिष्ठ संरक्षक हमारा देश हमारा अभिमान पत्रिका

शुभकामनाएं कर्ता : अर्चना वाजपेयी, अध्यक्ष ,पंडित लक्ष्मी नारायण शिक्षा प्रसार एवं सामाजिक कल्याण समिति

शुभकामनाएं कर्ता : शिव दयाल धाकड़ एसडीएम, पिछोर, शिवपुरी

शुभकामनाएं कर्ता : डॉक्टर दिनेश प्रसाद एवं समस्त हॉस्पिटल परिवार

शुभकामनाएं कर्ता : दीपक शुक्ला तहसीलदार, अशोकनगर

समस्त प्रदेश एवं देशवासियों को

15 अगस्त
स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक शुभकामनाएं...

शुभकामनाएं कर्ता : राकेश कुमार सगर, पुलिस अधीक्षक (द्वतीय बाहिनी), ग्वालियर

समस्त प्रदेश एवं देशवासियों को

15
AUGUST
स्वतंत्रता दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं

शुभकामनाएं कर्ता : कौशलेंद्र विक्रम सिंह, कलेक्टर, भोपाल

समस्त प्रदेश एवं देशवासियों को...

15 August

स्वतंत्रता दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं

शुभकामनाएं कर्ता : अमित सांघी, डीआईजी, ग्वालियर संभाग

समस्त प्रदेश एवं देशवासियों को

15 AUGUST

स्वतंत्रता दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं

शुभकामनाएं कर्ता
राजेश कुमार त्रिपाठी (भा.पु.से)
पुलिस उपायुक्त (अपराध)
नगरीय पुलिस, इंदौर

समस्त प्रदेश एवं देशवासियों को
15
AUGUST
स्वतंत्रता दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं
श्रीमती निवेदिता गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, सिंगरौली

समस्त प्रदेश एवं देशवासियों को
15
AUGUST
स्वतंत्रता दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं
श्रीमती रेणु बाला चतुर्वेदी (सरपंच उचाड़)

जयराज कुबेर, एसपी अजाक, ग्वालियर

कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, डबरा

देश के बाजारों में दाल-सब्जी से ज्यादा अंडे और मछली, मीट की बढ़ी डिमांड

हाल ही में लोकसभा के सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी ने पशुधन उत्पाद की डिमांड का मामला उठाया था। इसी के संबंध में सरकार ने नीति आयोग की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए आंकड़े पेश किए हैं। सरकार का कहना है कि, देश में मीट उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहा है। जबकि मछली का उत्पादन करीब 174 लाख टन पर पहुंच गया है।

इन दिनों देश में सब्जी-अनाज की डिमांड कम हो रही है। जबकि मछली और अंडे की डिमांड में पहले की तुलना में इजाफा होते दिख रहा है। केंद्र सरकार ने संसद में एक सवाल के जवाब में इससे संबंधित आंकड़े भी पेश किए है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में अंडे-मछली और मीट की डिमांड बढ़ने के आंकड़े सामने रखे हैं। इन आंकड़ों मुताबिक साल 2011-12 के मुकाबले साल 2021-22 में मछली की डिमांड 33 फीसद बढ़ी है। जबकि अंडे की डिमांड में 47 फीसद का इजाफा हुआ है। सभी तरह के मीट डिमांड 31 फीसदी तक बढ़ी है। इस आंकड़े को सरकार ने अनुमान के तौर पर बताया है। हाल ही में लोकसभा के सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी ने पशुधन उत्पाद की डिमांड का मामला उठाया था। इसी के संबंध में सरकार ने नीति आयोग की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए आंकड़े पेश किए हैं। सरकार का कहना है कि, देश में मीट उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहा है। जबकि मछली का उत्पादन करीब 174 लाख टन पर पहुंच गया है। कोरोना के बाद से इसमें और तेजी देखी जा रही है। पशुपालन से जुड़े प्रोडक्ट का योगदान बढ़ रहा है। सरकार का कहना है कि, बीते साल देश में 14 हजार करोड़ अंडों का उत्पादन हुआ था। जबकि मीट का उत्पादन एक करोड़ टन हुआ था। इसमें चिकन की हिस्सेदारी करीब 50 लाख टन थी। वहीं मछली का उत्पादन 174 लाख टन पर पहुंच गया है। जबकि झींगा भी 10 लाख टन को पार कर चुका है। पशुपालन मंत्रालय की एक रिपोर्ट बताती है कि, बीते साल के मुकाबले 25 करोड़ मुर्गों को प्रोडक्शन बढ़ गया है। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि साल 2021-22 में 306 करोड़ मुर्गों का चिकन खाया गया था। इस चिकन की मात्रा 48 लाख टन थी। जबकि साल 2022-23 में 331 करोड़ मुर्गों का 50 लाख टन चिकन खाया गया है।

जुलाई में वेज थाली के दाम 11 फीसदी हुए महंगे- टमाटर की बढ़ती कीमतों का असर खाने पर दिखाई देने लगा है। जुलाई के महीने में शाकाहारी थाली 11 प्रतिशत तक महंगी हो गई। संस्था क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस की मासिक रोटी चावल दर रिपोर्ट के मुताबिक, जून 2024 की तुलना में जुलाई में मांसाहारी थाली भी छह प्रतिशत महंगी हो गई है। रोटी, सब्जियां (प्याज, टमाटर और आलू), चावल, दाल, दही और सलाद वाली शाकाहारी थाली की कीमत जुलाई 2024 में 32.6 रुपये प्रति प्लेट थी जबकि जून 2024 में इसकी दर 29.4 रुपये प्रति प्लेट थी।

संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक, जून की तुलना में जुलाई महीने में शाकाहारी थाली की कीमतों में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसका मुख्य कारण टमाटर की कीमतों में उछाल आना था। इसका शाकाहारी थाली की कीमत बढ़ोतरी में सात प्रतिशत योगदान रहा है।मांसाहारी थाली की कीमत भी जुलाई के महीने में छह प्रतिशत बढ़कर 61.4 रुपये प्रति प्लेट हो गई जबकि जून में इसकी कीमत 58 रुपये प्रति प्लेट थी। मांसाहारी थाली में अमूमन शाकाहारी थाली वाली सामग्री ही होती है लेकिन उसमें दाल की जगह चिकन होता है।

आधार कार्ड से लिंक कराई जाएगी प्रॉपर्टी

जिले में प्लाट, जमीन के खसरे आधार से लिंक कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब तक ग्रामीण क्षेत्र के 10 प्रतिशत किसानों ने खसरे को आधार से लिंक करा लिया है। जबकि शहरी क्षेत्र में लिंकिंग का काम नहीं हो रहा है। जिले की बैरसिया, हुजूर और कोलार तहसील में तीन लाख 35 हजार से अधिक खसरों को लिंक किया जाना है, जबकि दो लाख से अधिक बंटान भी दर्ज नहीं किए गए हैं।

ऐसे में बंटान होने पर इन खसरों को भी आधार से लिंक किया जाएगा। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की सख्ती के बाद तहसील क्षेत्र के गांवों में शिविर लगाए जा रहे हैं। गांवों में पटवारी खुद जाकर खसरे को आधार से लिंक करा रहे हैं। कई गांवों में शिविर भी लगाए जा रहे हैं, जहां खसरा लिंक करने का काम किया जा रहा है। कोलार के सुहागपुर में पिछले एक हफ्ते से शिविर लगाया गया है। अधिकारियों का तर्क है कि शहरी क्षेत्र में खसरे को आधार से लिंक कराने में जमीन मालिक आनाकानी कर रहे हैं। जबकि गांवों में इतनी दिक्कत नहीं आ रही है। हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में सभी पटवारियों को भेजा गया है। खसरे से आधार लिंकिंग का काम चल रहा है।

15 अगस्त 1947... भारत के लिए स्वर्णिम दिवस

स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है, जिसे हम प्रतिवर्षा 15 अगस्त का मनाते हैं। यह पर्व हमें उन वीरों तथा क्रांतिकारियों की याद दिलाता है, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता तथा हमारे स्वर्णिम आज के लिए अपने जीवन को न्यौछावर किया।

यह एक पवित्र अवसर है, जब हम एकता, अखंडवा और भाइचारा तथा देश के प्रति निष्ठा एवं भक्ति की शपथ लेते हुए स्वतंत्रता दिवस को मनाकर इसके महत्व, औचित्य एवं इसकी पवित्रता को अक्षुण्ण रख सकते हैं।

15 अगस्त 1947 भारत वर्ष के इतिहास का स्वर्णिम दिवस है, उस दिन सैकड़ों वर्षों की पराधीनता के बाद प्रातः कालीन सूर्य की किरणें, पक्षियों का कलरव एवं अमृत रूपी नदियों की कल-कल करती प्रवाण ध्वनि देश के लिए एक नया संदेश लेकर आई। लाल किले पर अंग्रेजों के झण्डे के स्थान पर साहस, बलिदान, त्याग, सत्यनिष्ठा, समृद्धि, प्रगति और गतिशीलता का प्रतीक भारत का गौरवमयी तिरंगा झण्डा लहराया। सम्पूर्ण भारतवर्ष खुशियों के प्रवाह में बह रहा था, उस दिन हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक कहलाए।

पराधीनता एक जघन्य अभिशाप है जो किसी भी राष्ट्र के भविष्य, उत्साह, योजनाओं एवं उर्जा को समाप्त करता है। हम पराधीन भारतवर्ष के इतिहास के पृष्ठों को पलटते हैं तो ज्ञात होता है कि 1600 ई. में ईस्ट इंडिया कम्पनी मात्र व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई थी और उसी समय से हारे देश का भाग्य चक्र विपरीत दिशा में चला गया। 1757 ई. का पलासी युद्ध हमारी स्वतंत्रता का अवसान था। पलासी युद्ध में विजय प्राप्ति उपरान्त अंग्रेजों ने भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने हेतु हरसंभव प्रयास किया तथा 100 वर्ष बाद 1857 ई में ईस्ट इंडिया कम्पनी विघटित कर ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अपना प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर दिया। इसके पश्चात ही हमारे कष्टों, दुखों और यातनाओं को गति दिनी दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई।

हम पर अनेक काले कानून थोंपे गए, हमसे कर के रूप में प्रचुर मात्रा में धन राशि वसूल की गई। विरोध की आवाज उठाने पर अंग्रेजों ने बड़ी सख्ती एवं क्रूरता के साथ उसका दमन किया। हमारे नेतागण, नौजवान तथा बच्चों को या तो मौत के घाट उतारा गया या उन्हें जेलों क्रूरतम यातनाएं दी गई। किन्तु हमारे स्वतंत्रता के दीवाने झुके नहीं।

सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं
हम अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं।

डॉ. शालिनी कौशिक, वरिष्ठ संरक्षक
हमारा देश हमारा अभिमान

सचमुच हमारे वीरों ने सर नहीं झुकाए भले ही खुद को मिटा दिया। बाल गंगाधर तिलक, सरदार भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, लाला लाजरात राय, सुभाषचन्द्र बोस आदि शूरवीर हंसते-हंसते देश की आजादी की बलिदेवी पर न्यौछावर हो गए।

सरदार भगत सिंह ने फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए कहा-
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
वक्त आने पर बता देंगे ऐ आसमां।
अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।

गांधीजी का सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, बाल गंगाधर तिलक का गृह शासन आंदोलन, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, भारत से ब्रिटिश सरकार को समाप्त करने हेतु किए जा रहे थे। जिन्हें कठोरतापूर्वक दबाने की पूरी चेष्टा की गई किन्तु भारतीयों को कृतसंलग्न आत्मा को कबूल नहीं सके। परिणामस्वरूप, ब्रिटिश सरकार को भारतीय मांगों को स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा।

प्रतवर्ष 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। स्कूलों, कालेजों तथा सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण किया जाता है। दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सलामी दी जाती है।

आज हमारे देश में भ्रष्टाचार का साम्राज्य, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाई-भतीजावाद एवं धार्मिक उन्माद जैसी कुप्रवृत्तियां पनप रही है, जो हमारे देश की समृद्ध संस्कृति एवं गौरवशाली परम्पराओं को धीरे-धीरे नष्ट कर रही है। इस वर्ष हमारा पूरा देश आजादी के इस महोत्सव को वकसित भारत की थीम के रूप में भव्य तरीके से पूरे उत्साह और उमंग के साथ मना रहा है। इस थीम का उद्देश्य 15 अगस्त 2047 को आजादी के 100वें वर्ष का उत्सव मनाते हुए भारत वर्ष को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है।

हम सभी भारतीयों को जाति, धर्म, सम्प्रदाय, क्षेत्रवाद तथा आपसी वैमनस्यता का परित्याग कर समझ और सदभावना के साथ मिलकर देश को सशक्त, समृद्धि और उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर ले जाना है।

हमें अपने देश की समस्त बुराइयों एवं कुप्रवृत्तियों को दूर कर सर्वांगीण विकास के लिए कृत-संकल्प लेना होगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के सम्मुख सच्चे मन से शपथ लेनी होगी कि हम अपने महान देश भारत में किसी भी प्रकार के अलगावावादी तत्वों को प्रोत्साहन नहीं देंगे। हम अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए तन, मन, धन को न्यौछावर कर देंगे। स्वतंत्रता दिवस मनाने का यही हमारा वास्तविक संकल्प होगा और तभी उसका सही औचित्य होगा।

पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं.. जय हिन्द... जय भारत...

प्रतिष्ठान : धन लक्ष्मी वेयर हाउस चीनोर रोड डबरा, वैभव लक्ष्मी बेयर हाउस चीनोर रॉड डबरा

शिवराज सिंह
केन्द्रीय कृषिमंत्री

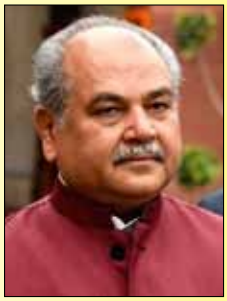

नरेंद्र सिंह तोमर
पूर्व केंद्रीय मंत्री

ज्योतिरादित्य सिंधिया
केंद्रीय मंत्री

नरोत्तम मिश्रा
पूर्व गृह मंत्री

विवेक शेजवलकर
पूर्व सांसद, ग्वालियर

इमरती देवी
पूर्व मंत्री (मप्र)

जितेन्द्र गुप्ता
मैनेजिंग डायरेक्टर महाकाल ऐग्रो फूड्स प्रा. लि.
प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा युवा मोर्चा (मप्र)

15 AUGUST
स्वतंत्रता दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं

महाकाल एग्रो फूड्स प्रा. लि.,
उच्च क्वालिटी के चावल निर्माता की ओर से

मुन्नालाल गुप्ता
महाकाल ग्रुप
अध्यक्ष गल्ला उद्योग एवं व्यापार संघ डबरा

समस्त प्रदेश एवं देशवासियों को

15 AUGUST
स्वतंत्रता दिवस
की हार्दिक शुभकामनाएं

डॉ. सुनील शर्मा (एमएस)
फेको एवं रेटीना सर्जन
फेलो एस.एस.जी. हॉस्पिटल,
राजकोट, रजि. नं. MP-4058

डॉ. अदिति शर्मा (एमएस)
ग्लूकोमा सर्जन
फैलो अरविंद आई हॉस्पिटल, मदैरे
रजि. नं. MP-4874

118, कैलाश विहार, इनकम टैक्स ऑफिस के सामने, सत्कार गेस्ट हाउस के पीछे,
सिटी सेंटर, ग्वालियर (मप्र) फोन नं. 0751-4922350
Email : dr.sunilsharma41077@gmail.com

समस्त प्रदेश एवं देशवासियों को

15 August
स्वतंत्रता दिवस
हार्दिक शुभकामनाएँ

बधाईकर्ता : श्रीमती शीतला पटले, कलेक्टर नरसिंहपुर

समस्त प्रदेश एवं देशवासियों को

बधाईकर्ता : सुमन गुर्जर, पुलिस अधीक्षक, पीटीएस तिघरा, ग्वालियर

श्री द्वारिका प्रसाद पलिया
दादाजी

श्री शिवम पलिया
बड़े पौत्र

श्री सत्यम पलिया
छोटे पौत्र

अनूप शर्मा
मैनेजिंग डायरेक्टर, इंजीनियर

समस्त प्रदेश एवं देशवासियों
को स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक शुभकामनाएँ

मैसर्स पलिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के संरक्षक श्री द्वारिका प्रसाद पलिया एवं उनके पुत्र मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियर अनूप शर्मा तथा पौत्र इंजिनियर शिवम शर्मा,सत्यम शर्मा एवं समस्त पलिया कंस्ट्रक्शन

समस्त प्रदेश एवं देशवासियों को

15 August

स्वतंत्रता दिवस

हार्दिक शुभकामनाएँ

बधाईकर्ता : ऋषभ गुप्ता, कलेक्टर, देवास

समस्त प्रदेश एवं देशवासियों को

15 August

स्वतंत्रता दिवस

की हार्दिक शुभकामनाएं

दिव्यांशु चौधरी
डबरा एसडीएम एवं प्रशासक, डबरा कृषि उपज मंडी

अनिल शर्मा
सचिव, डबरा कृषि उपज मंडी

मंत्री कश्यप का बयान, विजयवर्गीय बोले- हर सिस्टम का अल्टरनेट जरूरी

इंदौर शहर की पहचान अब नवाचारों के लिए होने लगी

इंदौर की पहचान अब अभिनव प्रयासों के लिए होने लगी है। हर जगह बात आती है पब्लिक सर्विस हम सर्विसेज को डिलीवर कैसे करते हैं। डिजिटाइजेशन से ही भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सकती है... डिजिटाइजेशन लोकतंत्र की संजीवनी है...

इंदौर नगर निगम द्वारा आयोजित हैकथॉन प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में उद्योग मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा कि राजनीति में मेरा पहला परिचय कैलाश विजयवर्गीय से ही हुआ था वो मेरे राजनीति गुरु हैं। जबसे कैलाश विजयवर्गीय जी ने महापौर के तौर पर काम करना शुरु किया था से नए नए प्रयोग सामने आने लगे। आज लोगों को बड़ी-बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए नगर निगम या नगरी निकाय से ही उम्मीदें होती हैं।

इंदौर की पहचान अब अभिनव प्रयासों के लिए होने लगी है। हर जगह बात आती है पब्लिक सर्विस हम सर्विसेज को डिलीवर कैसे करते हैं। डिजिटाइजेशन से ही भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सकती है। डिजिटाइजेशन लोकतंत्र की संजीवनी है।

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 5-6 दिन पहले पूरा सिस्टम फेल होने से दुनिया भर के जहाज रुक गए। जनता की इच्छा व सेवा के लिए सिस्टम के माध्यम से काम किया जाता है, इसके साथ ही सिस्टम फेल हो तो उसका भी अल्टरनेट सिस्टम होना चाहिए, इसीलिए चिंतन मंथन लगातार चलते रहना चाहिए।

मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इंदौर देश की सबसे स्वच्छ, स्मार्ट सिटी होने के साथ ही नवाचार के लिए प्रसिद्ध है। इंदौर हमेशा चैलेंज के साथ काम करता है। इंदौर को डिजिटल सिटी बनाने और नगर निगम की सुविधाओं और योजनाओं को डिजिटल प्लेटफार्म पर लाने के उद्देश्य से आयोजित हैकथॉन में देश के 1500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए थे।

इनमें से कई शहरों के 79 से ज्यादा यूनिवर्सिटी, कॉलेज के 500 से ज्यादा स्टूडेंट, एक्सपर्टस का चयन हुआ है। इनके द्वारा इंदौर नगर निगम के लिए ऐसे प्लेटफार्म के निर्माण किया जाएगा। इसके माध्यम से शहर के नागरिक निगम की सुविधाएं तुरंत और संतुलित रूप से प्राप्त कर सके।

महापौर ने कहा कि इंदौर के डिजिटाइजेशन की आधारशिला आज रखी जा रही है। हैकथॉन प्रतियोगिता के माध्यम से नगर निगम 42 से ज्यादा विभागों के माध्यम से किए जाने वाले कामों का बेहतर तौर पर निराकरण के संबंध में सुझाव प्राप्त किए जाएंगे। प्रतियोगिता में शामिल होने वाले प्रतिभागियों के माध्यम से निगम द्वारा ऐसे डिजिटल प्लेटफार्म को तैयार किया जाएगा। इसमें इनोवेटिव आइडियाज लिए जाएंगे।

हैकथॉन प्रतियोगिता निगम, ई-नगर पालिका और अन्य ई-गवर्नेंस पोर्टलों द्वारा वास्तविक चुनौतियों को समाधान देने का उद्देश्य से आयोजित की गई है। हैकथॉन में शामिल समाधानों और सुझावों को नगर निगम द्वारा आने वाले नए पोर्टल के आरएफ़पी (Request for Proposal) में शामिल किया जाएगा। यह निगम की अन्य प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में योगदान देगा। इंदौर इस पहल को लागू करने वाला पहला शहर होगा। प्रतियोगिता युवा रचनात्मक दिमागों, तकनीकी उत्साही और समाधान सलाहकारों को एक मंच के रूप में साबित होगी ।

चौराहे क्रॉस करने में नहीं लगेगी देर...

इंदौर में 100 से ज्यादा ट्रैफिक सिग्नल का बदलेगा समय

इंदौर शहर में बिगड़ रही यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए बड़ी कवायद चल रही है। यातायात पुलिस सौ से ज्यादा चौराहों और रास्तों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग बदलाव करने की तैयारी में है। प्रमुख चौराहों पर रोटरी बनाने की योजना तैयार की गई है। इस बदलाव में एसजीएसआईटीएस कॉलेज के इंजीनियर को भी शामिल किया है। इस कवायद का मकसद शहर के ट्रैफिक को सुधारना है, ताकि जाम न लगे और वाहन चालक बेफिक्र होकर गुजर सकें। इस सिलसिले में पुलिस आयुक्त राकेश गुप्ता ने बुधवार को शहर के ट्रैफिक अफसरों के साथ बैठक की।

एसीपी ने प्रजेंटेशन के माध्यम से उन चौराहों की स्थिति बताई, जहां ट्रैफिक का दबाव अधिक रहता है। सबसे ज्यादा दिक्कत मधुमिलन चौराहा की थी। वाहनों के भीषण जाम की तस्वीर देखकर तय हुआ कि चौराहे पर दो रोटरी और दो सिग्नल बनाए जाएंगे।

इसके पूर्व एसजीएसआईटीएस कॉलेज के इंजीनियर और ट्रैफिक पुलिस की टीम दौरा करेगी। स्कीम-140 स्थित अंडर बायपास की व्यवस्था सुधारने के लिए आइलैंड तोड़ने की योजना बनाई है। इसी तरह स्टार चौराहा से देवासनाका तक का दबाव कम करने के लिए भारी वाहनों को एमआर-11 से निकाला जाएगा।

हालांकि, इस रोड पर चौड़ीकरण का प्रस्ताव भी बनाया गया है। डीसीपी (ट्रैफिक) अरविंद तिवारी के मुताबिक आजादनगर चौराहा पर तो रोटरी में खामी है। इसके कारण यातायात का दबाव व्हाइट चर्च तक आता है। नई रोटरी आईआरसी के मानकों के अनुसार बनाई जाएगी। आयुक्त के मुताबिक छावनी चौराहा पर वाहन उलझते हैं। इस चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस स्टडी करेगी। अग्रसेन चौराहा और मधुमिलन चौराहा से आने-जाने वाले वाहन सुगमता से निकाले जाएंगे। इंदिरा गांधी प्रतिमा से छावनी तक जगह कम है। अतिक्रमण हटाकर लेफ्ट टर्न डिवाइडर बनाने का प्रस्ताव बनाया है। एसीपी किरण शर्मा ने कहा कि जीपीओ चौराहा पर बिजली के पोल हटाने हैं। रोड मार्किंग और कैट आई की आवश्यकता है।

समय आ गया है, जब देश समान नागरिक संहिता की जरूर समझे : हाई कोर्ट

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने 3 तलाक से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि 3 तलाक असंवैधानिक और समाज के लिए बुरा है। कानून निर्माताओं को यह समझने में कई साल लग गए। अब समय आ गया है कि देश समान नागरिक संहिता की आवश्यकता को समझे। समाज में आज भी आस्था और विश्वास के नाम पर कई कट्टरपंथी, अंधविश्वासी और अति-रूढ़िवादी प्रथाएं प्रचलित हैं।

संविधान में अनुच्छेद- 44 का भी जिक्र : भारत के संविधान में पहले ही से अनुच्छेद-44 शामिल है, जो समान नागरिक संहिता की वकालत करता है, किंतु अब इसे केवल कागज पर नहीं बल्कि वास्तविक बनाया

जाए। अच्छी तरह से तैयार समान नागरिक संहिता ऐसे अंधविश्वासों और बुरी प्रथाओं पर रोक लगाने का काम करेगी। इससे राष्ट्र की अखंडता को मजबूती मिलेगी।

न्यायमूर्ति अनिल वर्मा ने मप्र के बड़वानी जिले के राजपुर कस्बे की मुस्लिम महिला के तीन तलाक के मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। महिला ने मुंबई निवासी पति, सास और ननद के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई थी। महिला के पति ने उसे 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया था। न्यायमूर्ति वर्मा ने 10 पेज के फैसले में 3 तलाक को गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि इसमें शादी को कुछ ही सेकंड में तोड़ा जा सकता है और वह समय वापस नहीं लाया जा सकता। दुर्भाग्य से यह अधिकार केवल पति के पास है। अगर पति अपनी गलती सुधारना भी चाहे, तो निकाह-हलाला के अत्याचारों को महिला को ही झेलना पड़ता है।

भारत की आर्थिक प्रगति को रोकने हेतु अशांति फैलाने के हो रहे हैं प्रयास...

केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक क्षेत्र में लागू की गई कई नीतियों के चलते भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन ही गया है और अब यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

भारत की लगातार तेज हो रही आर्थिक प्रगति पर विश्व के कुछ देश अब ईर्ष्या करने लगे हैं एवं उन्हें यह आभास हो रहा है कि आगे आने वाले समय में इससे उनके अपने आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इस सूची में सबसे ऊपर चीन का नाम उभर कर सामने आ रहा है। और फिर, चीन की अपनी आर्थिक प्रगति धीमी भी होती जा रही है। दूसरे, विश्व को भी आज यह आभास होने लगा है कि विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के मामले में केवल चीन पर निर्भर रहना बहुत जोखिम भरा कार्य है। इसका अनुभव विशेष रूप से विकसित देशों ने कोरोना महामारी के बाद से वितरण चैन में आई भारी परेशानी से किया है, जिसके चलते इन देशों में मुद्रा स्फीति की समस्या आज भी पूरे तौर पर नियंत्रण में नहीं आ पाई है। साथ ही, चीन की विस्तारवादी नीतियों के चलते उसके अपने किसी भी पड़ोसी देश से (पाकिस्तान को छोड़कर) अच्छे सम्बंध नहीं हैं। अतः कई देश अब यह सोचने पर मजबूर हुए हैं कि चीन+1 की नीति का अनुपालन ही उनके हित में होगा। अर्थात, यदि किसी उद्योगपति ने चीन में अपनी एक विनिर्माण इकाई स्थापित की है तो आवश्यकता पड़ने पर उसके द्वारा अब दूसरी विनिर्माण इकाई चीन में स्थापित न करते हुए इसे अब किसी अन्य देश में स्थापित किया जाना चाहिए। यह दूसरा देश भारत भी हो सकता क्योंकि भारत अब न केवल "ईज आफ डूइंग बिजनेस" के क्षेत्र में अतुलनीय सुधार करता हुआ दिखाई दे रहा है बल्कि भारत में बुनियादी ढांचा के विस्तार में भी अतुलनीय प्रगति दृष्टिगोचर है।

केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक क्षेत्र में लागू की गई कई नीतियों के चलते भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन ही गया है और अब यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अर्थ के कई क्षेत्रों में तो भारत विश्व में प्रथम पायदान पर आ भी चुका है। इससे अब चीन के साथ अमेरिका को भी आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर अपने प्रभाव में कमी आने की चिंता सताने लगी है। अतः विश्व के कई देशों में अब भारत की आर्थिक प्रगति को लेकर ईर्ष्या की भावना विकसित होती दिखाई दे रही है। इस ईर्ष्या की भावना के कारण वे भारत के लिए कई प्रकार की समस्याएं खड़ी करने का प्रयास करते दिखाई देने लगे हैं। यह समस्याएं केवल आर्थिक क्षेत्र में खड़ी नहीं की जा रही हैं बल्कि सामाजिक, राजनैतिक एवं आध्यात्मिक आदि क्षेत्रों में भी खड़ी करने के प्रयास हो रहे हैं।

सबसे पहिले तो कुछ देश प्रयास कर रहे हैं कि भारत में किस प्रकार सामाजिक अशांति फैलायी जाए। इसके लिए भारत की कुटुंब प्रणाली को तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। देश में विभिन्न टीवी चैनल पर इस प्रकार के सीरियल दिखाए जा रहे हैं जिससे परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच आपस में छोटी छोटी बातों में लड़ने को बढ़ावा मिल रहा है। इन सीरियल में सास को बहू से, ननद को देवरानी से, छोटी बहिन को बड़ी बहिन से, एक पड़ौसी को दूसरे पड़ौसी से, संघर्ष करते हुए दिखाया जा रहा है। इन सीरियल के माध्यम से भारत में भी पूंजीवाद की तर्ज पर व्यक्तिवाद को हावी होते हुए दिखाया जा रहा है। जबकि भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति हमें संयुक्त परिवार में आपस में मिलजुल कर रहना सिखाती है, त्याग एवं तपस्या की भावना जागृत करती है एवं परिवार के छोटे सदस्यों द्वारा अपने बड़े सदस्यों का आदर करना सिखाती है। इसके ठीक विपरीत पश्चिमी सभ्यता के अंतर्गत संयुक्त परिवार दिखाई ही नहीं देते हैं वे तो व्यक्तिगत स्तर पर केवल अपने आर्थिक हित साधते हुए नजर आते है। पश्चिमी देशों के इन प्रयासों से आज कुछ हद तक भारतीय समाज भी पश्चिमी सभ्यता की ओर आकर्षित होता हुआ दिखाई देने लगा है। आज विकसित देशों के परिवारों में बेटे के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात वह परिवार से अलग होकर अपना परिवार बसा लेता है। अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल भी नहीं कर पाता है। इसके चलते इन देशों में सरकारों को अपने प्रौढ़ वर्ग के नागरिकों के देखरेख करनी होती है और इनके लिए सरकार के स्तर पर कई योजनाएं चलानी पड़ती है। आज इन देशों में प्रौढ़ नागरिकों की संख्या के लगातार बढ़ते जाने से सरकार के बजट पर अत्यधिक विपरीत प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि भारत में संयुक्त परिवार की प्रथा के कारण ही इस प्रकार की कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है। अतः पश्चिमी देशों द्वारा भारत की कुटुंब प्रणाली को अपनाए जाने के स्थान पर इसे भारत में भी नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है।

दूसरे, कई देश अब भारत में सामाजिक समरसता के तानेबाने को भी विपरीत रूप से प्रभावित करने के प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेष रूप से हिंदू समाज में विभिन्न मत, पंथ मानने वाले नागरिकों को आपस में लड़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इन्हें आपस में बांटा जा सके और भारत में अशांति फैलायी जा सके तथा जिससे देश की आर्थिक प्रगति विपरीत रूप से प्रभावित हो सके। भारत के इतिहास पर नजर डालने पर ध्यान में आता है कि भारत में जब जब सामाजिक समरसता का अभाव दिखाई दिया है तब तब विदेशी आक्रांताओं एवं अंग्रेजों को भारत में अपना शासन स्थापित करने में आसानी हुई है। उन्होंने "बांटो एवं राज करो" की नीति के अनुपालन से ही भारत के कुछ भू भाग पर अपनी सत्ता स्थापित की थी। अब एक बार पुनः इसी आजमाए हुए नुस्खे को पुनः आजमाने का प्रयास किया जा रहा है। चाहे वह जातिगत जनगणना करने के नाम पर हो अथवा समाज के विभिन्न वर्गों को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर किये जाने वाले आंदोलनों की बात हो।

इस्लामिक देशों की अशांति से भारत को क्या सबक लेना चाहिए..?

देखा जाये तो यदि इस समस्या का समाधान निकालने पर ध्यान नहीं दिया गया तो मुश्किलें खड़ी होना तय है। इस संबंध में विश्व इतिहास के कुछ उदाहरणों से सबक लिया जा सकता है। पहले तुर्की, मिस्र और सीरिया में ईसाई बहुसंख्यक थे।

तुर्की अशांत है, यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, मिस्र अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, मालदीव अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है। देखा जाये तो दुनिया के अधिकतर इस्लामिक देश अशांत हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो कभी अखण्ड भारत का ही हिस्सा थे लेकिन इनकी दिक्कतें तभी शुरू हुईं जब यह इस्लामिक देश बने। जबकि हिंदू बहुल भारत में लोकतंत्र मजबूत और स्थिर रहा तथा देश के सेकुलर रहने से सभी धर्मों के लोग यहां पूरी आजादी के साथ अपने जीवन का निवर्हन करते हैं।

लेकिन भारत का साम्प्रदायिक सौहार्द्र उन अराजक तत्वों को भा नहीं रहा है जोकि 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र में तब्दील करने का एजेंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिये योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न इलाकों की डेमोग्राफी बदली जा रही है। रिपोर्टों के मुताबिक देश के 9 राज्यों, 200 जिलों और 1500 तहसीलों का जनसांख्यिकी अनुपात बिगाड़ा जा चुका है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने पिछले सप्ताह ही कहा था कि भारत में रोहिंग्या घुसपैठ काफी बढ़ गई है तथा जनसांख्यिकी में बदलाव आने का खतरा वास्तविक और गंभीर है। उन्होंने कहा था कि रोहिंग्या लगातार भारत-बांग्लादेश सीमा का इस्तेमाल करके भारत में आ रहे हैं और कई राज्य जनसांख्यिकीय बदलाव की समस्या का सामना कर रहे हैं।

देखा जाये तो यदि इस समस्या का समाधान निकालने पर ध्यान नहीं दिया गया तो मुश्किलें खड़ी होना तय है। इस संबंध में विश्व इतिहास के कुछ उदाहरणों से सबक लिया जा सकता है। पहले तुर्की, मिस्र और सीरिया में ईसाई बहुसंख्यक थे। लेकिन आज यह इस्लामिक राष्ट्र हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की अच्छी खासी आबादी थी जोकि अब न्यूनतम स्तर पर पहुँच गयी है। ईरान में 90% पारसी थे और उसका नाम पर्सिया था लेकिन आज वह इस्लामिक देश है और वहां कट्टरपंथी सोच वाली सरकार है। वैश्विक घटनाक्रमों पर नजर डालेंगे तो यह भी प्रतीत होगा कि कम कट्टरपंथियों वाले देश और ज्यादा कट्टरपंथियों वाले देश के हालात में क्या फर्क होता है।

अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, इटली, नॉर्वे आदि में कट्टरपंथियों की आबादी 2 प्रतिशत से भी कम है इसलिए वहां दंगे इत्यादि नहीं होते। डेनमार्क, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन और थाईलैंड में कट्टरपंथियों की आबादी 5 प्रतिशत तक है इसलिए वहां आपको अक्सर छोटी-छोटी बातों पर धरना प्रदर्शन होने की खबरें मिलती होंगी। फ्रांस, फिलिपींस, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, त्रिनिदाद और टोबैगो आदि में कट्टरपंथियों की आबादी 10 प्रतिशत तक है इसलिए वहां विशेष दर्जा और तमाम सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन होते हैं। गुयाना, भारत, इज़राइल, केन्या और रूस आदि में इनकी आबादी 10 से 20 प्रतिशत तक है तो विशेष धार्मिक कानून, विशेष स्कूल, विशेष तालीम और विशेष ड्रेस कोड लागू करने पर जोर दिया जाता है। कट्टरपंथियों की आबादी का प्रतिशत जिन देशों में 20 प्रतिशत से ज्यादा है वहां अपहरण, बलात्कार, सामूहिक धर्मांतरण, आगजनी, नरसंहार, गृहयुद्ध जैसी स्थितियों के चलते बड़ी संख्या में लोगों का पलायन भी होता है। ऐसे देशों में बोस्निया, लेबनान, अल्बानिया, मलेशिया, कतर, सूडान, बांग्लादेश, मिस्र, गाजा, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, जॉर्डन, मोरक्को, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, सीरिया, तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सोमालिया और यमन आदि शामिल हैं।

अगर इन उदाहरणों से भी बात आपकी समझ में नहीं आई है तो कुछ और उदाहरणों को देखना चाहिए। जैसे कि दुर्योधन का ननिहाल गंधार अब अफगानिस्तान कहलाता है। भरत जी का ननिहाल कैकेय अब पाकिस्तान कहलाता है। ईस्ट बंगाल अब बांग्लादेश कहलाता है। वेस्ट पंजाब अब पाकिस्तान का हिस्सा है। आगे चल कर भारत को और कोई दिक्कत पेश नहीं आये इसलिए अभी से सख्त कदम उठाना जरूरी है। लेकिन सवाल उठता है कि हमारे सभी जनप्रतिनिधि कब देश की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देंगे। देखा जाये तो आज वास्तविक समस्या महंगाई या बेरोजगारी नहीं बल्कि जनसंख्या का बिगड़ता अनुपात है। आंकड़े बताते हैं कि भारत के 9 राज्यों अर्थात 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है।

इसको थोड़ा और विस्तार से देखेंगे तो भारत के 200 ज़िलों अर्थात 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसको और थोड़ा विस्तार से देखेंगे तो पाएंगे कि भारत की 1500 तहसीलों अर्थात 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। यही नहीं, सीमाई इलाकों की 300 तहसीलों अर्थात 100% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। साथ ही देश में ऐसा कोई जिला नहीं बचा है जहां घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट नहीं हो रहा है। बहरहाल, भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संसद में बताया है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना सदमे में हैं। देखा जाये तो सदमा होना स्वाभाविक भी है क्योंकि अचानक से उन्हें सत्ता और देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा।

क्लीनिकल ट्रायल की जरूरत नहीं; सरकार का बड़ा फैसला

अब जल्द मिल सकेंगी गंभीर बीमारियों की विदेशी दवाएं

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय संघ में कुछ श्रेणियों की अनुमोदित दवाओं के जरूरी नैदानिक परीक्षणों को भारत में छूट दी है। केंद्र सरकार ने विदेशी दवाओं को लेकर गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है। अब अगर कोई दवा अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय संघ (ईयू) में किए गए नैदानिक परीक्षण (क्लीनिकल ट्रायल) में सफल होती है और उसे वहां के दवा नियामक से मंजूरी मिल जाती है, तो उस दवा के लिए भारत में क्लीनिकल ट्रायल की जरूरत नहीं होगी। यानी गंभीर बीमारियों की दवाओं की बिक्री भी सीधे भारत में हो सकेगी।

यह छूट केवल पांच श्रेणी में दी गई है। इनमें दुर्लभ बीमारियों की दवाएं, जीन और सेसुलर थेरेपी उत्पाद, महामारी की स्थिति में उपोयग की जाने वाली नई दवाएं, विशेष रक्षा उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली नई दवाएं और महत्वपूर्ण चिकित्सीय प्रगति वाली नई दवाएं शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के इस फैसले के बाद कैंस, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (एसएमए) और डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (डीएमए) जैसी दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए दवाओं की शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। डीजीसीआई ने इसको लेकर सात अगस्त एक आदेश जारी किया। इसमें कहा गया, 'नई औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम 2019 के नियम 101 के मुताबिक, केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण, केंद्र सरकार की मंजूरी से समय-समय पर अध्याय-X के तहत नई दवाओं के अनुमोदन के लिए स्थानीय क्लीनिकल ट्रायल की छूट पर विचार करने और नियमों के अध्याय-V के तहत क्लीनिकल ट्रायल के संचालन की अनुमति देने के लिए देशों के नाम निर्दिष्ट कर सकता है।

एक अधिकारी ने बताया कि अब तक औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अमेरिका, ब्रिटेन और ईयू की पहले से अनुमोदित कई दवाएं भारतीय रोगियों के लिए तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। दरअसल, इन दवाओं के क्लीनिकल ट्रायल करना और भारत में विपणन (मार्केटिंग) करने से पहले सुरक्षा और प्रभावकारिता संबंधी आंकड़े तैयार करना बाकी है। हालांकि, नई औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम 2019 के नियम 101 के तहत डीसीजीआई को नई दवाओं की मंजूरी के लिए स्थानीय क्लीनिकल ट्रायल में छूट पर विचार करने के लिए देशों निर्दिष्ट करने की अनुमति है।

एक दूसरे का गुरुत्व बढ़ाना गुरु-शिष्य की श्रेष्ठतम परंपरा...

हालांकि गोरक्षपीठ की परंपरा, लोगों को शिष्य बनाने की नहीं है। पर, उत्तर भारत की प्रमुख व प्रभावी पीठ और अपने व्यापक सामाजिक सरोकारों के नाते इस पीठ के प्रति लाखों-करोड़ों लोगों की स्वाभाविक सी श्रद्धा है। गोरखपुर या यूं कह लें कि पूर्वांचल की तो यह अध्यक्षीय पीठ है।

एक दूसरे का गुरुत्व बढ़ाना गुरु-शिष्य की श्रेष्ठतम परंपरा है। गुरु का गुरुत्व, शिष्य की श्रद्धा में होता है। यह श्रद्धा गुरु के सशरीर रहने पर तो होती ही है, उनके ब्रह्मलीन होने पर भी शिष्य की श्रद्धा जस की तस रहती है। इसी तरह एक योग्य गुरु भी लगातार अपने शिष्य का गुरुत्व बढ़ाने का प्रयास करता है। इस मायने में गोरखपुर स्थित गोरक्षपीठ की तीन पीढियां खुद में बेमिसाल हैं।

अपने समय में योगी के लिए अपने गुरुदेव का आदेश 'वीटो पावर' होता था : गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ के प्रति उनकी श्रद्धा कितनी गहरी थी, इसके साक्षी पीठ से जुड़े लोग हैं। कम शब्दों में कहें तो अपने समय में ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ का आदेश उनके शिष्य योगी आदित्यनाथ के लिए 'वीटो पॉवर' जैसा था। आज भी पद के अनुरूप अपनी तमाम व्यस्तताओं में से समय निकालकर वह जब भी गोरखनाथ मंदिर पहुंचते हैं तो सबसे पहले अपने स्मृतिशेष गुरुदेव का ही आशीष लेते हैं। यह सिलसिला उनके मठ में रहने तक जारी रहता है। गुरु शिष्य का यही संबंध योगी जी के गुरुदेव और उनके गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ में भी था। लोगों को शिष्य बनाने की परंपरा नहीं, बावजूद लाखों लोग खुद को मानते हैं : हालांकि गोरक्षपीठ की परंपरा, लोगों को शिष्य बनाने की नहीं है। पर, उत्तर भारत की प्रमुख व प्रभावी पीठ और अपने व्यापक सामाजिक सरोकारों के नाते इस पीठ के प्रति लाखों-करोड़ों लोगों की स्वाभाविक सी श्रद्धा है। गोरखपुर या यूं कह लें कि पूर्वांचल की तो यह अध्यक्षीय पीठ है। पीठ का हर निर्णय अमूमन हर किसी को स्वीकार्य होता है। खासकर पर्व और त्योहारों के मामले में।

खिचड़ी मेला, गुरुपूर्णिमा और अन्य मौकों पर दिख जाती है ये श्रद्धा

समय-समय पर पीठ के प्रति यह श्रद्धा दिखती भी है। मकर संक्रांति से शुरू होकर करीब एक माह तक चलने वाला खिचड़ी मेला इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इस दौरान नेपाल, बिहार से लगायत देश भर के लाखों श्रद्धालु गुरु गोरखनाथ को, मौसम की परवाह किए बिना अपनी श्रद्धा निवेदित करने आते हैं। कुछ मन्नत पूरी होने पर आते हैं, कुछ नई मन्नत मांगने भी। गुरु पूर्णिमा के दिन भी जो भी पीठाधीश्वर रहता है, उसके प्रति श्रद्धा निवेदित करने बड़ी संख्या में लोग आते हैं।

सितंबर में गुरु शिष्य परंपरा की मिसाल बनती है गोरक्षपीठ

इसी तरह हर सितंबर में साप्ताहिक पुण्यतिथि समारोह के दौरान अपने गुरुओं को पीठ याद करती है। उनके कृतित्व, व्यक्तित्व, सामाजिक सरोकारों, देश के ज्वलंत मुद्दों पर अलग-अलग दिन संत और विद्वत समाज के लोग चर्चा करते हैं। यह एक तरीके से गुरुजनों को याद करने के साथ उनके संकल्पों को पूरा करने की भी प्रतिबद्धता होती है।

जिला न्यायाधीशों के पेंशन संबंधी मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया निर्देश

जल्द करें समाधान

उच्चतम न्यायालय ने जिला न्यायाधीशों को दी जा रही बहुत कम पेंशन से संबंधित मुद्दों का केंद्र से जल्द से जल्द समाधान करने को कहा। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ''हम जिला न्यायपालिका के संरक्षक होने के नाते आपसे (अटार्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से) आग्रह करते हैं कि आप न्यायमित्र के साथ बैठकर कोई रास्ता निकालें।''

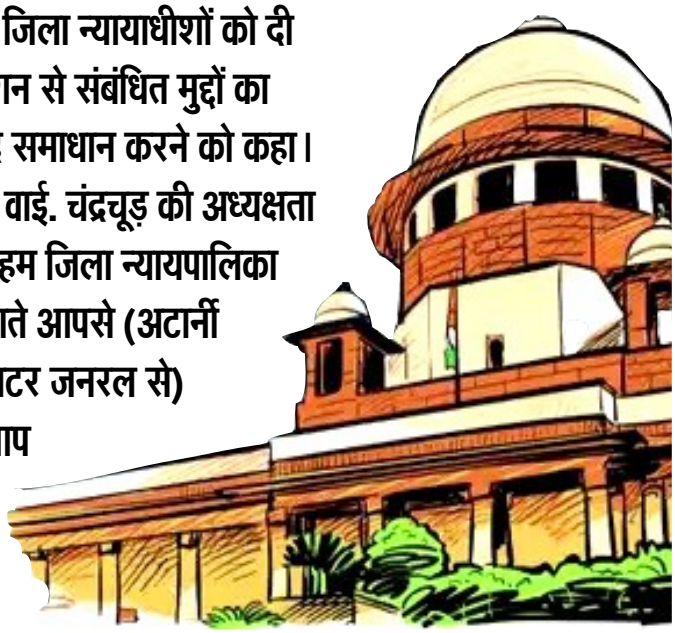

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि इनमें से कुछ मामले ''बहुत पेचीदा'' हैं। उन्होंने कैंसर से पीड़ित एक जिला न्यायाधीश के मामले का उल्लेख किया और कहा कि पेंशन से संबंधित शिकायतों को उठाते हुए जिला न्यायाधीशों द्वारा उच्चतम न्यायालय में कई याचिकाएं दायर की जा रही हैं। पीठ में न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। पीठ ने कहा, ''जिला न्यायाधीशों को केवल 15,000 रुपये पेंशन मिल रही है।

जिला न्यायाधीश उच्च न्यायालयों में आते हैं और आमतौर पर उन्हें 56 और 57 वर्ष की आयु में उच्च न्यायालयों में पदोन्नत किया जाता है और वे 30,000 रुपये प्रति माह पेंशन को लेकर सेवानिवृत्त होते हैं।'' प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि उच्च न्यायालय के बहुत कम न्यायाधीशों को मध्यस्थता के मामले मिलते हैं और 60 वर्ष की आयु होने पर वे वकालत भी नहीं कर सकते। केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जिला अदालत के न्यायाधीशों के पेंशन संबंधी मामले पर बहस करने के लिए कुछ समय मांगा। पीठ ने दलीलों पर गौर किया और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कल्याणकारी उपायों के क्रियान्वयन की मांग करने वाली अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ की याचिका पर सुनवाई 27 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। इस बीच न्यायमित्र के रूप में काम कर रहे वकील के. परमेश्वर ने उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया कि कई राज्यों ने न्यायिक अधिकारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के बकाया भुगतान पर द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) की सिफारिशों का अनुपालन किया है। न्यायमित्र ने पीठ को बताया कि अब राज्यों ने अनुपालन हलफनामे दाखिल करना शुरू कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की बकाया राशि के भुगतान पर एसएनजेपीसी की सिफारिशों का पालन न करने पर 11 जुलाई को कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य और वित्त सचिवों को तलब किया था। एसएनजेपीसी की सिफारिशों का पालन न करने पर अप्रसन्नता जाहिर करते हुए पीठ ने कहा था, अब हम जानते हैं कि अनुपालन कैसे कराया जाता है। पीठ ने कहा, हम उन्हें जेल नहीं भेज रहे हैं, लेकिन उन्हें यहीं रहने दीजिए, फिर हलफनामा दाखिल किया जाएगा। उन्हें अभी व्यक्तिगत रूप से पेश होने दीजिए। देशभर के न्यायिक अधिकारियों की सेवा शर्तों में एकरूपता की आवश्यकता पर बल देते हुए उच्चतम न्यायालय ने एसएनजेपीसी के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभ, वेतन, पेंशन और अन्य आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए प्रत्येक उच्च न्यायालय में दो-न्यायाधीशों की समिति के गठन का 10 जनवरी को निर्देश दिया था।

उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि अन्य सेवाओं के अधिकारियों ने एक जनवरी, 2016 को अपनी सेवा शर्तों में संशोधन का लाभ उठाया है जबकि न्यायिक अधिकारियों से संबंधित ऐसे ही मुद्दे अब भी आठ साल से अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। पीठ ने कहा था कि सेवा से निवृत्त हुए न्यायाधीश और जिन लोगों का निधन हो गया है, उनके पारिवारिक पेंशनभोगी भी समाधान का इंतजार कर रहे हैं। एसएनजेपीसी की सिफारिशों में जिला न्यायपालिका की सेवा शर्तों को निर्धारित करने के लिए एक स्थायी तंत्र स्थापित करने के मुद्दे से निपटने के अलावा वेतन संरचना, पेंशन और पारिवारिक पेंशन और भत्ते आदि के मुद्दे शामिल हैं।

शराब की दुकान के बाहर अंग्रेजी बोलना सीखें...

बैनर लगाने के कारण शराब दुकान मालिक पर जुर्माना

पोस्टर ने शराब की बिक्री को नयी ऊंचाई पर पहुंचाया या नहीं, लेकिन इसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके चलते दुकान मालिक को उपहास और आलोचना का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में एक शराब की दुकान के मालिक ने शराब पीने के बाद लोगों की अधिक भावुक हो जाने की सामान्य प्रवृत्ति को उजागर करके बिक्री बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी यह योजना विफल हो गयी और उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि शराब की दुकान के मालिक ने बुरहानपुर जिले के नाचनखेड़ा में अपनी दुकान के पास एक बैनर लगाया था, जिस पर लिखा था, दिनहाड़े अंग्रेजी बोलना सीखें। संदेश के नीचे एक तीर शराब की दुकान की ओर इशारा कर रहा था।

हालांकि, यह स्पष्ट नहीं था कि पोस्टर ने शराब की बिक्री को नयी ऊंचाई पर पहुंचाया या नहीं, लेकिन इसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके चलते दुकान मालिक को उपहास और आलोचना का सामना करना पड़ा।

एक अधिकारी ने बताया कि यह पूरा मामला शनिवार को जिला प्रशासन के पास भी पहुंचा। बुरहानपुर की जिलाधिकारी भव्या मित्तल ने बताया कि उन्होंने आबकारी विभाग को शराब विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

इसके बाद आबकारी अधिकारियों ने दुकान के लाइसेंस धारक को नोटिस जारी किया। अधिकारी ने बताया कि दुकान के मालिक के जवाब को असंतोषजनक बताते हुए अधिकारियों ने शराब लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

राशन दुकानों पर अब गेहूं के साथ ज्वार, बाजरा व रागी भी मिलेगी

मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा के अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों को राशन वितरण में अब श्रीअन्न के तहत राज्य में उत्पन्न होने वाले ज्वार, बाजरा और रागी भी दी जाएगी। इसके लिए स्थानीय किसानों से अनाज लेने और प्रक्रिया में स्व-सहायता समूहों को जोड़ने पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जिन्हें पर्ची जारी की गई है, वह योजना के लिए पात्र हैं या नहीं इसका भी सर्वे कराया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को मंत्रालय में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। बैठक में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, मुख्य सचिव वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा सहित अधिकारी उपस्थित थे।

'इंदौर रोड सिक्स लेन प्रोजेक्ट' शुरू करने के लिए कंपनी को भेजा अनुबंध करने का नोटिस, 46 किमी का हिस्सा बनेगा सिक्स लेन'इंदौर रोड सिक्स लेन प्रोजेक्ट' शुरू करने के लिए कंपनी को भेजा अनुबंध करने का नोटिस, 46 किमी का हिस्सा बनेगा सिक्स लेन

बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, फोर्टिफाईड चावल, शक्कर एवं नमक वितरण अनुसूचित जाति जनजाति विद्यार्थियों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने, वन-नेशन-वन राशन कार्ड, प्रधानमंत्री राशन आपके ग्राम योजना, मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, महिलाओं को 450 रुपये में गैस रिफिल उपलब्ध कराना, प्रधानमंत्री जनमन मिशन, गेहूं उपार्जन की स्थिति और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए जारी गतिविधियों पर प्रस्तुतिकरण के साथ चर्चा भी हुई।

राज्य स्तर पर गठित किया जाएगा गैस कारपोरेशन

मुख्यमंत्री ने कहा कि नापतौल विभाग के अमले की यूनिफार्म तय की जाए। अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि में इस संबंध में जारी व्यवस्था के आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने पाइप लाइन द्वारा रसोई गैस उपलब्ध कराने संबंधी गतिविधि के लिए राज्य स्तर पर गैस कारपोरेशन गठित करने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में भी गैस उपयोग की संभावना है, अतः इसकी आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना बनाई जाए। अन्य राज्यों में इस संबंध में लागू व्यवस्था का भी अध्ययन किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए नीति बनाई जाए। साथ ही भू-जल भंडारण के संरक्षण और बिजली की बचत के दृष्टिगत बिना मौसम की धान व मूंग के उत्पादन को हतोत्साहित किया जाए। इसके लिए किसानों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से किसान सम्मेलन और कृषि विशेषज्ञों के साथ परिचर्चाएं भी की जाएं।

जिन उपभोक्ताओं ने 6 माह से नहीं लिया राशन उनका राशन दुकान से कट सकता है नाम...

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मध्य प्रदेश में एक करोड़ 11 लाख परिवारों के पांच करोड़ व्यक्तियों को प्रतिमाह पांच किलोग्राम खाद्यान्न फ्री दिया जा रहा है। जो उपभोक्ता लगातार छह महीने से राशन नहीं ले रहे हैं, अब उनके नाम उचित मूल्य की राशन दुकान के बाहर चस्पा किए जाएंगे।

इसके बाद भी यदि उपभोक्ता नहीं आते हैं तो उनका नाम सूची से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इससे जो स्थान रिक्त होगा, उस पर दूसरे पात्र व्यक्ति का नाम शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत प्रदेश में प्रतिमाह गेहूं और चावल का वितरण किया जाता है। पात्रग्राही को ही राशन मिले, इसके लिए बायोमैट्रिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है। कई उपभोक्ता राशन लेने नहीं आते- कई उपभोक्ता प्रतिमाह राशन लेने नहीं आते हैं। जो खाद्यान्न शेष रहता है, उसे दुकान संचालक द्वारा सुरक्षित रखा जाता है, लेकिन यह देखने में आ रहा है कि कई उपभोक्ता छह-छह माह

से खाद्यान्न लेने ही नहीं आ रहे हैं। इन सभी के नाम अब दुकान के बाहर सूचना पटल पर चस्पा किए जाएंगे ताकि आसपास के लोग देखकर उन्हें बता सकें। इसके बाद भी वे खाद्यान्न लेने नहीं आते हैं, तो यह माना जाएगा कि वे खाद्यान्न नहीं लेना चाहते हैं। ऐसे लोगों के नाम काटकर अन्य पात्र लोगों के नाम सूची में शामिल कर उन्हें पात्रता पर्ची जारी की जाएगी। इसके लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि छह-छह माह तक खाद्यान्न नहीं लेने वाले उपभोक्ताओं को चिह्नित करें। यदि वे किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं, तो ठीक वर्ना उनके नाम सूची से हटा दिए जाएं।

प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक सर्वेक्षण की सराहना की, बोले-

यह हमारे देश अर्थव्यवस्था की मौजूदा ताकत को दर्शाता है

आर्थिक सर्वेक्षण एक वार्षिक दस्तावेज़ है जिसे सरकार द्वारा केंद्रीय बजट से पहले अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाता है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक संभाग द्वारा आर्थिक समीक्षा तैयार की जाती है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण की सराहना की और कहा कि इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की 'मौजूदा ताकत' पर प्रकाश डाला गया है। यह टिप्पणी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में बजट पेश करने से एक दिन से भी कम समय पहले आई है। उन्होंने एक एक्स पोस्ट में लिखा कि आर्थिक सर्वेक्षण हमारी अर्थव्यवस्था की मौजूदा ताकतों पर प्रकाश डालता है और हमारी सरकार द्वारा लाए गए विभिन्न सुधारों के परिणामों को भी दर्शाता है। जैसे-जैसे हम विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यह आगे के विकास और प्रगति के क्षेत्रों की भी पहचान करता है।

आर्थिक सर्वेक्षण एक वार्षिक दस्तावेज़ है जिसे सरकार द्वारा केंद्रीय बजट से पहले अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाता है। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक संभाग द्वारा आर्थिक समीक्षा तैयार की जाती है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में तैयार किया जाता है। देश में पहली बार आर्थिक समीक्षा 1950-1951 में पेश की गई थी जब यह बजट दस्तावेजों का ही हिस्सा होती थी।

आर्थिक समीक्षा 2023-24 में कहा गया है कि तेज क्षमता वृद्धि, रोलिंग स्टॉक का आधुनिकीकरण और ऊर्जा दक्षता रेलवे के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में सोमवार को पेश आर्थिक समीक्षा में कहा गया हैतेज क्षमता और ऊर्जा दक्षता को ध्यान में रखते हुए समर्पित माल गलियारों, हाई-स्पीड रेल, वंदे भारत, अमृत भारत एक्सप्रेस, आस्था स्पेशल ट्रेनों जैसी आधुनिक यात्री सेवाओं, उच्च क्षमता वाले रोलिंग स्टॉक और अंतिम छोर तक रेल संपर्क जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दी गई है। इसमें कहा गया है कि रेलवे तीन प्रमुख गलियारों - उच्च यातायात घनत्व वाले गलियारे, ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारे, और रेल सागर (बंदरगाह संपर्क) गलियारे - के लिए परियोजनाओं की योजना बना रहा है ताकि रसद लागत और कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सके। समीक्षा में कहा गया है कि रेलवे ने अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को मुख्य रूप से अक्षय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करके अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की योजना बनाई है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि 2029-30 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता की स्थापना की अपेक्षित आवश्यकता लगभग 30 गीगा वाट है।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इतिहास रचते हुए लगातार 7वां बजट पेश किया...

निर्मला सीतारमण ने इतिहास रचते हुए लगातार 7वां केंद्रीय बजट संसद में पेश किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि शानदार रही। वित्त मंत्री सीतारमण भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। निर्मला सीतारमण ने इतिहास रचते हुए लगातार 7वां केंद्रीय बजट संसद में पेश किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि शानदार रही। वित्त मंत्री सीतारमण भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं।

सीतारमण देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं और उन्होंने जुलाई 2019 से अब तक पांच पूर्ण बजट और 1 फरवरी, 2024 को अंतरिम बजट पेश किया है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट पेश किए जाने से पहले संसद पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट पेश किए जाने के लिए मंच तैयार किए जाने के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में मौजूद हैं।

कारोबारी घरानों को बैंक खोलने की मंजूरी देने की योजना नहीं : दास

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय बैंक के पास फिलहाल कारोबारी घरानों को बैंक खोलने की मंजूरी देने की कोई योजना नहीं है। दास ने आर्थिक समाचारपत्र फाइनेंशियल एक्सप्रेस की तरफ से यहां आयोजित 'मॉडर्न' बीएफएसआई (बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा) सम्मेलन में कहा कि कारोबारी घरानों को बैंकों का प्रवर्तन करने की अनुमति देने से हितों के टकराव और संबंधित पक्षों के लेनदेन से जुड़ा जोखिम बढ़ जाता है। आरबीआई गवर्नर ने बैंकों के गठन की कारोबारी घरानों को मंजूरी देने संबंधी किसी योजना के बारे में पूछे जाने पर कहा, इस समय, उस दिशा में कोई विचार नहीं है।

आरबीआई ने लगभग एक दशक पहले बैंकों के लाइसेंस देने की प्रक्रिया के अंतिम दौर में कई बड़े कारोबारी समूहों को नए बैंकों का लाइसेंस देने के अयोग्य घोषित कर दिया था। हालांकि देश की वृद्धि आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूंजी जुटाने की कारोबारी घरानों की क्षमता को देखते हुए आरबीआई के एक कार्य समूह ने वर्ष 2020 में इस मुद्दे पर नए सिरे से चर्चा शुरू की थी। आरबीआई गवर्नर ने बैंक को अन्य व्यवसायों से इतर बताते हुए कहा कि दुनिया भर के अनुभव से पता चला

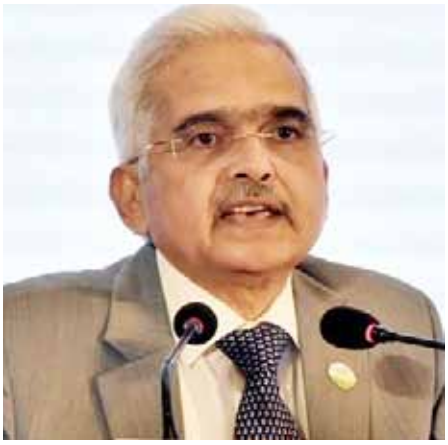

है कि यदि कारोबारी घरानों को बैंक खोलने की मंजूरी दी जाती है, तो हितों के टकराव और संबंधित पक्ष के लेन-देन से संबंधित मुद्दे आने की आशंका बनी होती है।

दास ने 1960 के दशक के अंत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले के दौर का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भारत में भी कारोबारी घराने बैंकिंग गतिविधियों में शामिल थे। दास ने कहा, दुनिया भर के अनुभव से पता चला है कि संबंधित पक्ष के लेन-देन की निगरानी करना या उन्हें विनियमित करना और रोकना बहुत मुश्किल होगा। इसमें शामिल जोखिम बहुत अधिक होते हैं। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को बढ़ने के लिए संसाधनों की जरूरत है, लेकिन हमें आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अधिक बैंकों की जरूरत नहीं है। आरबीआई गवर्नर ने कहा, भारत को बैंकों की संख्या में वृद्धि की जरूरत नहीं है।

भारत को मजबूत और अच्छी तरह से संचालित बैंकों की जरूरत है और हमें लगता है कि ये प्रौद्योगिकी की मदद से पूरे देश में बचत जुटाने और ऋण जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे। दास ने कहा कि सामान्य बैंकों के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया सदा सुलभ व्यवस्था के अंतर्गत है और इसके लिए आने वाले आवेदनों का स्वागत है। दास ने कहा कि निजी ऋण क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और वर्तमान में उच्च जोखिम उठाने वाले लोगों के लिए निवेश के एक आकर्षक मार्ग के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि आरबीआई इस क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा, हालांकि वर्तमान में जोखिम सीमित प्रतीत होते हैं, लेकिन यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि इन बाजारों में कमजोरियां और परस्पर जुड़ाव नकारात्मक झटकों को बढ़ा सकते हैं और वित्तीय स्थिरता संबंधी चिंताएं पैदा कर सकते हैं।

बिलौआ नगर परिषद की ओर से सभी नगर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं एवं अपील

1.स्वच्छता बनाये रखे, 2.जल, मकान, टेक्स समय पर जमा कराए 3. कचरा कचरा गाड़ी मैं ही डाले...

श्रीमती विजयलक्ष्मी चौरसिया
अध्यक्ष : नप बिलौआ

अनीता राम अवतार रावत
उपाध्यक्ष, बिलौआ

सुनील चौरसिया
पार्षद बिलौआ

पीयूष श्रीवास्तव
मुख्य नगर पालिका अधिकारी

अपीलकर्ता : नगरपालिका

विधायकों को मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश

अब हर सोमवार और मंगलवार भोपाल में रहें बीजेपी विधायक, मंत्रियों से करें मुलाकात...

प्रदेश के सभी बीजेपी विधायक अब हर सोमवार और मंगलवार को भोपाल में रहेंगे। भोपाल में रुककर ये विधायक अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री और मंत्री से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के जरिए विधानसभा क्षेत्रों के रोडमैप पर होने वाले काम की जानकारी देंगे। जिससे कामों में तेजी लाई जा सकेगी। मंत्रियों से भी कहा है कि वे विधायकों से मिलें और उनकी बातों को तवज्जो दें।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों के लिए पहले ही निर्देश दे रखे हैं कि वे सोमवार और मंगलवार को भोपाल में रहेंगे और इसके बाद जिलों में या क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। सोमवार और मंगलवार को आमतौर पर कैबिनेट की बैठक होती है। इसलिए मंत्रियों के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। इस बीच मंत्रियों की भोपाल में मौजूदगी के मद्देनजर विधायकों को भी इस दौरान भोपाल में रहने के लिए कहा है। सीएम यादव ने कैबिनेट बैठक में अनौपचारिक संवाद में मंत्रियों से कहा है कि सोमवार और मंगलवार को विधायक भोपाल में रहेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे तो उनकी बातों को सुनना और क्षेत्र के विकास व अन्य जरूरी समस्याओं के निराकरण का काम करना है।

अधिकारियों को भी निर्देश : विधायकों के सोमवार और मंगलवार को भोपाल में रहने के दौरान उनके क्षेत्र के मसलों को लेकर मंत्रालय और डायरेक्टोरेट के अफसरों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे उनकी बातों को सुनें। बताया जाता है कि मौखिक निर्देश के जरिए लागू की गई व्यवस्था के बाद अब बीजेपी विधायक हर सोमवार और मंगलवार को अपने क्षेत्र के रोडमैप और अन्य कार्यों को लेकर भोपाल में रुकने भी लगे हैं।

विधायकों के साथ बैठक में उठा था मसला

सीएम मोहन यादव ने यह व्यवस्था पिछले माह विधायकों के साथ संभागवार की गई बैठकों के बाद लागू की है। बताया जाता है कि कई विधायकों ने मंत्रियों से मुलाकात नहीं हो पाने और तवज्जो नहीं मिलने का मसला संभागवार बैठक के दौरान उठाया था। इसके बाद सीएम यादव ने मंत्रियों को भी कहा कि विधायकों की सुनें और विधायकों को भी सोमवार व मंगलवार को भोपाल में रुककर क्षेत्र विकास के काम कराने के लिए कहा है।

नगरवासियों एवं देश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की
हार्दिक शुभकामनाएं

// अपील //

- निकाय द्वारा जारी कम्प्यूटरीकृत सम्पात्तिकर/जलकर एवं अन्य करों के बिल प्राप्त होने पर यथा समय बिल की राशि जमा कराकर अधिभार से बचें।
- जल ही जीवन है, जल का दुरुपयोग न करें।
- भवन स्वामी अपने-अपने भवनों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग संरचना बनाकर जल स्तर बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें।
- नगर पालिका की भूमि एवं शासकीय भूमि पर अतिक्रमण न करें।
- नगर को सुन्दर एवं स्वच्छ बनाने में नगर पालिका का सहयोग करें, कचड़ा नियत स्थानों पर ही डालें
- जन्म-मृत्यु का पंजीयन, समय पर करायें, तथा निकाय से कम्प्यूटरीकृत जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

श्रीमती लक्ष्मी देवी
अध्यक्ष,नगर पालिका परिषद डबरा

सत्येन्द्र दुबे
उपाध्यक्ष,नगर पालिका परिषद डबरा

प्रदीप भदौरिया
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद डबरा

कार्यालय नगर पालिका परिषद, डबरा जिला-ग्वालियर (म.प्र.)

हालात ठीक होने पर बांग्लादेश लौट सकती हैं शेख हसीना

हसीना के बेटे वाजेद जॉय बोले- अपने लोगों को नहीं छोड़ेंगे...

सजीब वाजेद जॉय ने कहा कि 'हां, यह सच है कि मैंने कहा था कि वह बांग्लादेश वापस नहीं लौटेंगी, लेकिन देश भर में हमारे नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं पर लगातार हमलों के बाद पिछले दो दिनों में बहुत कुछ बदल गया है।' शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली के बाद शेख हसीना वापस लौटेंगी। सजीब ने बांग्लादेश में जारी हिंसा और अराजकता के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को जिम्मेदार ठहराया। जॉय ने कहा कि शेख हसीना निश्चित रूप से बांग्लादेश वापस लौटेंगी, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि वह सक्रिय राजनेता के तौर पर लौटेंगी या फिर राजनीति से सेवानिवृत्ति के बाद। सजीब ने कहा कि शेख मुजीब के परिवार के सदस्य न तो अपने लोगों को छोड़ेंगे और न ही संकटग्रस्त आवामी लीग को। सजीब ने अपनी मां की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली के लिए अंतरराष्ट्रीय

स्तर पर आम राय बनाने के लिए भारत से दबाव बनाने की अपील की। गौरतलब है कि सजीब वाजेद ने अपने हालिया बयान में कहा था कि शेख हसीना बांग्लादेश वापस नहीं लौटेंगी। हालांकि अब सजीब ने उसके उलट बयान दिया है।

सजीब वाजेद जॉय ने कहा कि 'हां, यह सच है कि मैंने कहा था कि वह बांग्लादेश वापस नहीं लौटेंगी, लेकिन देश भर में हमारे नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं पर लगातार हमलों के बाद पिछले दो दिनों में बहुत कुछ बदल गया है। अब हम अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जो भी करना होगा, करेंगे; हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। अवामी लीग बांग्लादेश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, इसलिए हम अपने लोगों से दूर नहीं जा सकते। लोकतंत्र बहाल होने के बाद वह निश्चित रूप से बांग्लादेश वापस आएगी।'

शेख हसीना के बेटे सजीब ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने का साथ ही कानून व्यवस्था बहाल करने की अपील की। साथ ही उम्मीद जताई कि देश में लोकतंत्र बहाल होगा और नए चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि देश अराजकता की तरफ बढ़ रहा है और दूसरा अफगानिस्तान बनने की राह पर है। उन्होंने कहा, 'आप बांग्लादेश की राजनीति से अवामी लीग को कभी बाहर नहीं कर सकते। उनके (मोहम्मद यूनुस) व्यक्तिगत विचार चाहे जो भी हों, उन्होंने कहा है कि वह एकता की सरकार चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तथा अतीत की गलतियों को भविष्य पर हावी नहीं होने देना चाहते। मुझे उम्मीद है कि वह अपने वचन पर कायम रहेंगे।'

शुभकामनाकर्ता : विवेक शर्मा, डबरा एसडीओपी

शुभकामनाकर्ता : यशवंत गोयल, थाना प्रभारी डबरा

डेयरी किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का 15000 करोड़ का निवेश...

डेयरी किसानों की आय बढ़ाने, केंद्र सरकार का 15000 करोड़ रुपये का निवेश – मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय देशभर के गांवों में डेयरी किसानों की आजीविका सुधारने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रहा है। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को नवीनतम पद्धतियों और तकनीकों की जानकारी देकर उनके काम को आसान और लाभदायक बनाना है।

पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम में खुरपका-मुंहपका और ब्रुसेलोसिस जैसी पशु बीमारियों के नियंत्रण के लिए सहायता देने तथा पशुधन के अन्य संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों को दी जा रही है। इस योजना में किसानों के घर-द्वार पर गुणवत्तापूर्ण पशुधन स्वास्थ्य सेवाएं के लिए सचल पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित की जाती हैं। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) के तहत सरकार 15000 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है। इस निधि का उद्देश्य डेयरी प्रसंस्करण, मांस प्रसंस्करण, चारा विनिर्माण, वैक्सीन उत्पादन, पशु अपशिष्ट प्रबंधन और नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है।

केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने राज्य सभा में जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन

कार्यक्रमों में प्रजनन शिविर, दूध उत्पादन प्रतियोगिता, बछड़ा स्वास्थ्य में सुधार सम्मेलन और किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। किसानों को लिंग-पृथक्कृत वीर्य के साथ कृत्रिम गर्भाधान (एआई), बोवाइन इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) और जीनोमिक चयन जैसी नवीनतम तकनीकों से अवगत कराया जा रहा है।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत भेड़, बकरी और सूकरों में कृत्रिम गर्भाधान की नवीनतम तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही हरा चारा उत्पादन, परिरक्षित चारा बनाने, चारा काटने और पशुओं के लिए कुल मिश्रित भोज्य सामग्री को बढ़ावा दे रहा है। डेयरी विभाग ने किसानों के लिए ई-गोपाला ऐप भी प्रारंभ किया है, यह ऐप किसानों को पशुओं के संतुलित आहार के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है।

समस्त प्रदेश एवं देशवासियों को

15 August
स्वतंत्रता दिवस
हार्दिक शुभकामनाएँ

अपील

- स्वच्छता बनाए रखे
- कचरा कचरे पेटी मैं ही डाले
- नगरपालिका एवं शासकीय भूमि पर अतिक्रमण ना करे

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, आंतरी

उपाध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, आंतरी

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, आंतरी

शुभकामनाकर्ता : आंतरी नगरपालिका परिषद

सरकार करेगी ड्रोन उड़ाना सीखने में मदद, मिलेगी सब्सिडी और खेती कार्यों में मदद

समय के साथ कृषि का फील्ड भी आधुनिक हो गया है। अब इस फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। साथ ही खेती के कार्यों में ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। जिसके चलते देश में ड्रोन पायलट की मांग भी बढ़ रही है। राजस्थान सरकार की तरफ से ड्रोन पायलट को ट्रेन करने के लिए भी मदद की जा रही है। सरकार की ओर से अब ड्रोन उड़ाना सीखने वालों को सब्सिडी दी जाएगी। ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग के लिए उम्र सीमा 18 साल से लेकर 65 साल तय की गई है। जबकि आवेदन को 10वीं क्लास पास भी होना चाहिए। राज्य भर में 500 लोगों को ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। अप्लाई करने वालों का सिलेक्शन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। हर जनपद से अधिक से अधिक 10 प्रशिक्षणार्थियों को ड्रोन उड़ाने के प्रशिक्षण के लिए सब्सिडी दी जाएगी।

देश भर में खेती में उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा है। जिसके साथ ही ड्रोन पायलटों की मांग भी तेजी से बढ़ी है। राजस्थान की सरकार राज्य में ड्रोन को बढ़ावा देने का काम कर रही है। ड्रोन चलाने के लिए ट्रेंड पायलट की आवश्यकता को देखते हुए राजस्थान राज्य की सरकार 10वीं पास लोगों को कृषि विभाग की तरफ से ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दिला रही है।

कितनी है फीस : रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रेनिंग कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में दी जाएगी। रिमोट पायलट के 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के लिए 50,000 रुपये फीस तय की गई है। हालांकि चयनित उम्मीदवारों को 9 हजार 300 रुपये का ही भुगतान करना होगा। इसमें 5 हजार रुपये प्रशिक्षण व 4,300 रुपये आवास व खाने का खर्च है। तय शुल्क का 50 प्रतिशत कृषि विभाग और 50 फीसदी राशि में से 20,000 ये कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय वहन करेगा।

कैसे करें अप्लाई : आवेदक को राज किसान साथी पोर्टल या राज किसान सुविधा एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 10वीं और समकक्ष की मार्कशीट स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है। कृषक उत्पादक संगठन या कस्टम हायरिंग केंद्र द्वारा नामित होने पर, नामांकन प्रमाण पत्र की एक स्कैन की हुई प्रति अपलोड करनी होगी। प्रशिक्षण के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

समस्त प्रदेश एवं देशवासियों को

15 August
स्वतंत्रता दिवस
हार्दिक शुभकामनाएँ

अपील

- स्वच्छता बनाए रखे
- कचरा कचरे पेटी मैं ही डाले
- नगरपालिका एवं शासकीय भूमि पर अतिक्रमण ना करे

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, मोह

उपाध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, मोह

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, मोह

शुभकामनाकर्ता : मोह नगरपालिका परिषद

एनडीए सरकार का कृषि पर फोकस...

किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत...

केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में कृषि और किसान संबंधी कामकाज पर एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार खेती के लिए एक स्पष्ट रोडमैप बनाकर काम कर रही है और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

असंभव को संभव बनाना

श्री चौहान ने कहा कि उनकी सरकार ने असंभव को संभव करके दिखाया है। उन्होंने मध्यप्रदेश में नर्मदा-क्षिप्रा रिवर लिंकिंग परियोजना का उदाहरण दिया और बताया कि कैसे 20 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई हो रही है। उन्होंने कहा कि सिंचाई उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता है और केन-बेतवा परियोजना को भी स्वीकृति मिल चुकी है।

फसल बीमा योजना में बदलाव : श्री चौहान ने कहा कि मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की जिससे किसानों को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि 2023-24 में 8 करोड़ 69 लाख आवेदन आए हैं, जबकि कांग्रेस के समय पर लागू फसल बीमा के तहत केवल 3 करोड़ 51 लाख आवेदन आते थे। उन्होंने अऋणी किसानों पर अपनी बात रखते हुए कहा की "वहीं, कांग्रेस के समय पर केवल 20 लाख अऋणि किसान बीमा करवाते थे और अब 5 करोड़ 48 लाख आए हैं।

उत्पादन में वृद्धि : उन्होंने कहा कि सरकार ने सिंचाई के अच्छे प्रयास किए हैं और उत्तम बीज तैयार किए हैं और जानकारी दी की सरकार 109 नए बीज जारी करने वाली है। जलवायु अनुकूल बीज और बेहतर सिंचाई के माध्यम से कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही है। खाद्यान्न उत्पादन की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया की वर्ष 2023-24 में खाद्यान का उत्पादन 329 मिलियन टन और बागवानी का उत्पादन 352 मिलियन टन तक पहुंच गया है।

खेती के 6 प्रमुख सूत्र : श्री चौहान ने बताया कि NDA सरकार की कृषि नीति के 6 प्रमुख उद्देश्य हैं: उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के उचित दाम देना, प्राकृतिक आपदा में किसानों को राहत राशि देना, कृषि का विविधीकरण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। इन्ही सूत्रों पर आगे अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा की खेती में वैल्यू एडिशन और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती सुरक्षित रहे, इसलिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार खेती का रोडमैप बनाकर काम कर रही है।

बासमती राइस का निर्यात

धान के निर्यात पर श्री चौहान ने बताया कि भारत का बासमती राइस कनाडा और अमेरिका में धूम मचा रहा है। उन्होंने कहा कि 46 हजार करोड़ रुपए का बासमती राइस एक्सपोर्ट किया गया है। जब बाजार में किसान को फसलों के अच्छे दाम मिलेंगे, तो वह एमएसपी पर अपनी फसल क्यों बेचेगा।

यूरिया-डीएपी पर सब्सिडी

श्री चौहान ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों को सस्ता खाद उपलब्ध कराया है। उन्होंने बताया कि सरकार 2366 रुपए का यूरिया किसानों को 266 रुपए में देती है और डीएपी का बैग 2433 रुपए की बजाय 1350 रुपए में मिल रहा है।

बीएसएनएल के ग्राहकों की संख्या बढ़ रही, स्वदेशी 4जी नेटवर्क तैयार- श्री सिंधिया

केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को कहा कि सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कंपनी का घरेलू 4जी नेटवर्क भी तैयार है और इसे 5जी में बदलने का काम चल रहा है। यहां संवाददाताओं से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत स्वदेशी तकनीक वाला 4जी नेटवर्क तैयार है और कुछ महीनों में बीएसएनएल के माध्यम से इसकी सेवाएं पूरे देश में उपलब्ध होंगी।

सिंधिया ने कहा, कई लोगों ने पूछा था कि जब जियो, एयरटेल और वोडाफोन ने 4जी नेटवर्क शुरू किया तो बीएसएनएल ने क्यों नहीं? यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प था कि अगर हमें सरकारी कंपनी का नेटवर्क विकसित करना है तो हम चीन या किसी अन्य विदेशी देश के उपकरणों का उपयोग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यह निर्णय लिया गया कि स्वदेशी तकनीक विकसित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया दिन में ग्वालियर पहुंचे और बाद में मुरैना जाकर एक मंदिर में पूजा-अर्चना की। सिंधिया ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत संकल्प लिया है कि भारत अपना खुद का 4जी स्टैक, कोर सिस्टम या टावर विकसित करेगा जिसे रेडिएशन एक्सेस नेटवर्क (आरएएन) कहा जाता है।

भारत अपनी तकनीक विकसित करेगा और देशवासियों को 4जी नेटवर्क देगा और इसमें हमें डेढ़ साल लग गए। भारत अपनी स्वदेशी तकनीक रखने वाला पांचवां देश बन गया है। टावर लगाने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि तेजस नेटवर्क, सी-डॉट और टीसीएस जैसी भारतीय कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं और बीएसएनएल इसे लागू कर रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, हम अक्टूबर के अंत तक 80,000 टावर लगा देंगे और बाकी 21,000 अगले साल मार्च तक लगा देंगे। ...यानी मार्च, 2025 तक 4जी नेटवर्क के एक लाख टावर लगा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे तेजी से डाउनलोड करने और टेलीविजन देखने में मदद मिलेगी। हम इस 4जी कोर पर 5जी का उपयोग कर सकते हैं। हमें 5जी सेवाओं के लिए टावरों में कुछ बदलाव करने होंगे और इस पर काम चल रहा है। हम जल्द ही 4जी से 5जी तक का सफर पूरा कर लेंगे।

रामजानकी राजेश पण्डा
अध्यक्ष नगर परिषद पीछोर

इरफान खान, उपाध्यक्ष
नगर परिषद पीछोर

पीयूष श्रीवास्तव, मुख्य
नपा अधिकारी, पीछोर

सभी पिछोर नगर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

अपील

1. निकाय द्वारा जारी कंप्यूटरीकृत संपत्ति कर जलकर एवं अन्य करों के बिल प्राप्त होने पर समय बिल की राशि जमा कराकर अधिभार से बचें।
2. जल ही जीवन है जल का दुरुपयोग ना करें।
3. भवन स्वामी अपने-अपने भवनों में रूफ़ वाटर हार्वेस्टिंग संरचना बनाकर जलस्तर बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें।
4. नगर पालिका की भूमि एवं शासकीय भूमि पर अतिक्रमण ना करें।
5. नगर को सुंदर एवं स्वच्छ बनाने में नगरपालिका का सहयोग करें कचरा नियत स्थानों पर ही डालें।
6. जन्म मृत्यु का पंजीयन समय पर कराएं तथा निकाय से कंप्यूटरीकृत जन्म / मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करें।
7. नगर पालिका से अनुमति प्राप्त कर ही भवन निर्माण करें।
8. शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लें।
9. नगर में वृक्षारोपण कर नगर को हरा भरा बनाने में सहयोग प्रदान करें।

14 वर्ष में दुनिया में तीन गुना बढ़े विरोध-प्रदर्शन

भारत में सबसे बड़ा आंदोलन किसानों का रहा

जर्नल नेचर में प्रकाशित इस अध्ययन के मुताबिक, अहिंसक विरोधों का हिंसक विरोधों की तुलना में अधिक प्रभाव पड़ता है और अन्य परिणामों के अलावा राजनीतिक शासन को बदलने में ये अधिक प्रभावी होते हैं। अध्ययन के अनुसार, 2006 से 2020 के बीच हुए विरोध प्रदर्शनों का विश्लेषण बताता है कि 2020 के दौरान भारत में किसानों का विरोध सबसे बड़ा था।

दुनियाभर में 2006 के बाद विरोध-प्रदर्शनों की संख्या तीन गुना से अधिक बढ़ गई है। इन बढ़ते हुए विरोध प्रदर्शनों का कारण राजनीति, कृषि, सरकारी या गैर सरकारी अन्याय, असमानता और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे हैं।

जर्नल नेचर में प्रकाशित इस अध्ययन के मुताबिक, अहिंसक विरोधों का हिंसक विरोधों की तुलना में अधिक प्रभाव पड़ता है और अन्य परिणामों के अलावा राजनीतिक शासन को बदलने में ये अधिक प्रभावी होते हैं। अध्ययन के अनुसार, 2006 से 2020 के बीच हुए विरोध प्रदर्शनों का विश्लेषण बताता है कि 2020 के दौरान भारत में किसानों का विरोध सबसे बड़ा था। अन्य प्रमुख विरोधों में 2010 के अरब स्प्रिंग, ऑक्युपाई आंदोलन और 2020 में वैश्विक ब्लैक लाइव्स मैटर विरोध शामिल हैं। इसी कड़ी में जारी इस्राइल-हमास संघर्ष के बाद से हजारों की तादाद में विरोध-प्रदर्शन हुए हैं।

एकजुट मांगों के कारण मिलती है सफलता

अध्ययन में 2010 में टेक बैक पार्लियामेंट अभियान का उदाहरण दिया है, जिसका उद्देश्य चुनावी सुधार था। इसे एकजुट मांगों के कारण सफलता मिली और समन्वित नारों और मांगों के साथ उसी संगठनात्मक रूप ने 2011 में यूके के जनमत संग्रह को प्रभावित किया। यह 2011 में ऑक्युपाई लंदन से अलग है, जहां विरोध प्रदर्शनों में असमानता, वित्तीय विनियमन, जलवायु परिवर्तन और उत्पीड़न को संबोधित करने के लिए कई मांगें शामिल थीं। हालांकि, इनमें सामंजस्य की कमी थी।

300 प्रदर्शन राष्ट्रीय नेताओं को पदों से हटाने के लिए

अध्ययन से पता चलता है कि 1900 से 2006 के बीच 300 विरोध प्रदर्शन और क्रांतिकारी अभियान राष्ट्रीय नेताओं को पदों से हटाने के मकसद से किए गए थे। मिसाल के तौर पर फिलीपीन की पीपुल्स पावर क्रांति जैसे अहिंसक विरोध प्रदर्शन 1986 में तानाशाह फर्डिनेंड मार्कोस को हटाने में सफल रहे।

3.5 फीसदी लोगों को संगठित करने वाले अभियान सफल

अध्ययन में अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक एरिका चेनोवेथ के हवाले से कहा गया है कि हर आंदोलन जिसने आबादी के कम से कम 3.5 फीसदी लोगों को संगठित किया वह सफल रहा। यानी विरोध-प्रदर्शन से बदलाव सुनिश्चित करने के लिए इस स्तर की भागीदारी की जरूरत होती है।

4 गांव से निकलेगा वेस्टर्न रिंग रोड का 8 किमी हिस्सा...

आठ हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी...

बाइपास महू के एबी रोड से शुरू होकर शिप्रा के समीप पूर्वी बाइपास से जुड़ जाएगा...

इंदौर के पश्चिमी रिंग बाइपास को बनाने की कवायद तेज हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने गुरुवार को छह लेन मार्ग के लिए जमीन अधिगृहण की अधिसूचना जारी की है। बाइपास 64 किलोमीटर लंबाई में बनेगा। पहले चरण में महू से हातोद तक के हिस्से में काम होगा।

फिलहाल आठ किलोमीटर हिस्से की जमीन पहले चरण में ली जा रही है। बाइपास का आठ किलोमीटर हिस्सा देपालपुर तहसील के किशनपुरा,ललेंडीपुरा, बेटर्मा खुर्द और मोहना गांव से होकर गुजरेगा। चारों गांवों की 8.1257 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता सडक़ बनाने के लिए लगेगी। इसमें से 13 जगहों पर सरकारी जमीन है, जबकि 43 निजी जमीनों का अधिगृहण होगा।बाइपास के लिए 19 गांवों की 400 एकड़ जमीन सडक़ निर्माण के लिए लगेगी। इसके बनने से आगर-मुबंई राजमार्ग के वाहन, इंदौर अहमदाबाद, इंदौर नागपुर हाइवे, इंदौर चित्तौडग़ढ़ हाइवे की तरफ जा सकेंगे। एनएचएआई इसे दो हिस्सों में बनाएगा। अभी महू से हातोद तक के 34 किलोमीटर हिस्से में काम शुरू होगा। बाइपास महू के एबी रोड से शुरू होकर शिप्रा के समीप पूर्वी बाइपास से जुड़ जाएगा।

इसके बनने से शहर में बाइपास की रिंग तैयार हो जाएगी। इंदौर में 24 साल पहले पूर्वी बाइपास बना था। इस प्रोजेक्ट पर डेढ़ हजार करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी। इस बाइपास को पीथमपुर से भी कनेक्ट किया जाएगा। इस बाइपास में चार बड़े ब्रिज और 15 से ज्यादा छोटे ब्रिज बनेंगे। तीन साल में इसका काम पूरा होगा। एनएचएआई इस बायपास पर टोल भी वसूलेगा।

हर विधानसभा के लिए एक शव वाहन की व्यवस्था

शहर के नागरिकों को आवश्यकता पडऩे पर अब इंदौर नगर निगम के द्वारा मात्र 200 रु. में शव वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। इस बारे में निगम परिषद की बैठक में प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। अब इसका संचालन शुरू किया जाएगा। शहर के नागरिकों को अपने घर में हुई मौत के बाद मृत व्यक्ति की देह को घर से श्मशान घाट दूर होने के कारण शव वाहन की मदद लेना पड़ती है। अभी शहर में बहुत सारे सामाजिक संगठनों और कुछ अस्पतालों के द्वारा शव वाहन चलाए जा रहे हैं ।

इसमें से कुछ का संचालन ता निशुल्क हो रहा है लेकिन अस्पतालों के द्वारा व्यावसायिक रूप से चलाए जा रहे हैं, उनके द्वारा इस कार्य के लिए हजारों रुपए की मांग संबंधित परिवार से की जाती है। ऐसे में शहर के नागरिकों को अभी भी शव वाहन की आवश्यकता महसूस हो रही है। नगर निगम के द्वारा पिछले दिनों अपनी वर्कशॉप में 6 मोक्ष रथ के रूप में शव वाहन तैयार करवाए गए। इन वाहन का मुख्यमंत्री के द्वारा डिजिटल लोकार्पण भी किया जा चुका है। अभी इनका संचालन शुरू होना शेष था। अभी तक संचालन इसलिए शुरू नहीं हो पा रहा था कि इसके लिए निगम के द्वारा नीति को मंजूरी देने का काम नहीं हो सका था।

हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक शव वाहन

हाल ही में हुई निगम परिषद की बैठक में कार्य सूची में शामिल इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब नगर निगम के द्वारा नागरिकों को 200 रु. में शव वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। हर विधानसभा क्षेत्र को एक शव वाहन अलग से आवंटित किया जा रहा है। मोक्ष रथ के नाम से यह शव वाहन नागरिकों की मदद करेगा। कल नीति का मंजूरी मिलने के साथ ही इस वाहन के संचालन का रास्ता साफ हो गया है।

भाजपा नेता प्रभात झा का लंबी बीमारी के चलते निधन...

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके प्रभात झा

मध्य प्रदेश के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता प्रभात झा का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जानकारी के अनुसार पिछले एक महीने से उनका दिल्ली में इलाज चल रहा था। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके झा पार्टी में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे।

राज्यसभा के पूर्व सदस्य और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का शुक्रवार सुबह गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार थे। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता प्रभात झा का शुक्रवार सुबह 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जानकारी के अनुसार पिछले एक महीने से उनका दिल्ली में इलाज चल रहा था। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके झा पार्टी में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने झा के निधन पर ट्विटर पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, 'भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री प्रभात झा के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। बाबा महाकाल दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिवार को इस दुःखद दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मध्य प्रदेश के विकास में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका हमें सदैव प्रेरित करती रहेगी। आपका निधन राजनीतिक जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है।'

भाजपा सूत्रों ने बताया किझा (67) के परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले झा बाद में भाजपा में शामिल हो गए और 2010 में पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बने। झा 2008 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने गए और 2020 तक उच्च सदन में रहे। उन्होंने 2015 में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया।

भारतीय सेना, दुनिया की बेहतरीन सेनाओं में से एक : मुख्यमंत्री

सीएम ने कारगिल विजय के रजत जयंती वर्ष पर शहीद स्तंभ भारत माता की प्रतिमा को नमन किया

हथियारों के आगे भी होता है हौसला जो दिलवाता है जीत, कारगिल की विजय, भारतीय सेना के शौर्य की पहचान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कारगिल विजय दिवस और रजत जयंती वर्ष पर भोपाल के शौर्य स्मारक में भारत माता की प्रतिमा पर नमन किया। डॉ. यादव ने शौर्य स्तंभ पहुंचकर शहीदों को नमन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शौर्य स्मारक परिसर में स्थापित सेना के टी-55 टैंक का लोकार्पण भी किया। शौर्य स्मारक में अब आमजन भी इस टैंक को देख सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने द्रोणाचार्य सभागार में कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और कार्यक्रम को संबोधित किया। राजधानी भोपाल में कारगिल विजय दिवस पर हुए मुख्य कार्यक्रम में आज शौर्य स्मारक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव के पहुंचने पर एनसीसी कैडेट्स ने गार्ड्स ऑफ ऑनर दिया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग सुदर्शन चक्र कोर, श्री प्रीतपाल सिंह, एनसीसी के मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल अजय कुमार के साथ ही 21 कोर भोपाल के अनेक अधिकारी भी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सेना एवं एनसीसी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कारगिल विजय से हमारी सेना ने एक नया इतिहास रचा। यह विजय भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की पहचान है। युद्धों में कई बार हथियारों के आगे सेना का हौसला महत्वपूर्ण होता है, जो जीत की ओर ले जाता है। पराक्रम भारत की पहचान रही है। दुश्मन हमारे देश में विभिन्न कारणों और तरीकों से नष्ट- भ्रष्ट करने के उद्देश्य से आते हैं, लेकिन हमारे शौर्य के आगे वे टिक नहीं पाते। मिस्र और रोम जैसी पुरानी सभ्यताएं खत्म हो गईं। लेकिन भारत की हस्ती मिटती नहीं है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बने। आज दोनों राष्ट्रों की तुलना करें, तो हम देखते हैं कि भारत की अच्छाईयां अलग स्थान दिलाती हैं। दोनों देशों के बीच 1965 और 1971 के बाद 1999 में युद्ध हुए। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, पड़ोसी ने आंखों में धूल झोंकी। भारत पड़ोसी धर्म का निर्वहन कर रहा था। हमने सदैव ही अपनी सीमाओं और मर्यादा को समझा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अतीत को देखते हुए समझा है कि पड़ोसी कैसे हैं और उनसे किस तरह व्यवहार करना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की पराजय हुई। आज भारत शत्रु के दुस्साहस का उत्तर उसके घर में घुसकर दे सकता है। भारतीय सेना दुनिया की बेहतरीन सेनाओं में से एक है, जो दुश्मन से निपटना जानती है। कारिगल शहीद सैनिकों को राष्ट्र कभी नहीं भुलाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों को कारगिल विजय दिवस की बधाई देते हुए युद्ध के शहीदों को नमन किया।

नगरीय सीमा में आने वाले उद्योगों को राहत, नहीं लगेगा संपत्ति कर

मध्य प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार अलग-अलग अधिनियमों में कई परिवर्तन कर रही है। नगरीय सीमा के भीतर आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों से दोहरा कर वसूला जाता है। नगरीय निकाय भी संपत्ति कर(प्रापर्टी टैक्स) लेते हैं और उन्हें लीज रेंट भी देना होता है। औद्योगिक संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई थी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर अब नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नगरीय निकायों की सीमा के भीतर आने वाले औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित इकाइयों को प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने जा रही है। हालांकि, इनसे सेवा शुल्क लिया जाएगा, जो अन्य क्षेत्रों की तुलना आधा होगा। इसके लिए टैक्स में छूट का प्रस्ताव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और वित्त विभाग से अभिमत लेकर कैबिनेट में अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

रोजगार बढ़ाने के लिए अनुकूल माहौल

प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए सरकार नियमों को उद्योगों को अनुकूल बना रही है। अभी नगरीय क्षेत्र की सीमा में आने वाले औद्योगिक केंद्रों में स्थापित उद्योगों से संबंधित नगरीय निकाय प्रापर्टी टैक्स लेते हैं। इसके लिए उन्हें मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 और मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 में प्रविधान हैं। जबकि, वर्ष 2013 में सरकार मध्य प्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंधन अधिनियम में यह प्रावधान कर चुकी है कि औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके बाद भी स्थानीय निकायों द्वारा न केवल टैक्स वसूला जा रहा है बल्कि न देने पर कार्रवाई भी हो रही है। विभिन्न औद्योगिक संगठन दोहरे कराधार को समाप्त करने की मांग सरकार से कर चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न औद्योगिक संगठनों के अलावा उद्योगपतियों से वन-टू-वन चर्चा भी कर रहे हैं। इसमें उन्होंने आश्वस्त किया है कि नियमों के कारण किसी उद्योगपति को प्रदेश में उद्योग लगाने में कठिनाई नहीं होगी।

टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव तैयार किया गया

मुख्यमंत्री की पहल के बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 163 और नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 132 के प्रावधान अनुसार उद्योगों को प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव तैयार किया है। सूत्रों का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित इकाइयों से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया जाएगा पर उन्हें सेवा शुल्क देना होगा। यह जलकर, स्वच्छता सहित अन्य सुविधाओं के लिए जो शुल्क देना होता है, वह अन्य क्षेत्रों की तुलना में आधा ही लगेगा।

इंदौर-दुबई की उड़ान बंद, शारजाह के लिए हफ्ते में 4 दिन चलेगी

इंदौर से दुबई की सीधी उडान को एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बंद कर दिया है। गुरुवार को यह उड़ान रात्रि में आखरी बार इंदौर पहुंची और देर रात दुबई के लिए रवाना हुई। विमान कंपनी ने इसकी आगामी तारीख की बुकिंग बंद कर दी है। इसके अलावा शारजाह की उडान के फेरे बढ़ाए गए है। अब शारजाह के लिए सप्ताह में चार दिन इंदौर से उडान मिल सकेगी। दुबई जाने वाले यात्रियों को शारजाह होकर जाना पड़ेगा। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से 30 मार्च 2023 को एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा दुबई की उड़ान शुरू की गई थी। करीब 17 माह बाद विमान कंपनी द्वारा दुबई की उडान को बंद कर दिया गया है। जानकारों का कहना है कि दुबई एयरपोर्ट पर सही स्लाट नहीं मिलने के कारण उड़ान को बंद किया गया है।

इसकी अपेक्षा विमान कंपनी सप्ताह में दो दिन चलने वाली शारजाह उडान को बढ़ाकर सप्ताह में चार दिन संचालित करेगी। यह उड़ान शारजाह से रविवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को इंदौर आएगी और इंदौर से सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को उड़ान वापस रवाना होगी।

शारजाह का कम फेरा

इंदौर और शारजाह के बीच एक अप्रैल 2023 में सप्ताह में तीन दिन एयर इंडिया एक्सप्रेस ने उडान शुरू की थी। शुक्रवार को दुबई की उड़ान भी संचालित होती थी। इस वजह से शारजाह की शुक्रवार की उड़ान को बंद कर दिया गया था। दोनों उड़ान एक ही दिन होने से शारजाह उड़ान को कम यात्री मिल रहे थे। वर्तमान में सप्ताह में दो दिन ही शारजाह उडान संचालित हो रही है।

शारजाह से दुबई जाना पड़ेगा

इंदौर से दुबई के लिए चलने वाली एकमात्र सीधी उडान की बुकिंग बंद हो चुकी है। इंदौर से यात्रियों को शारजाह पहुंचकर सड़क मार्ग से दुबई जाना होगा। इससे यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त राशि का भार भी पड़ेगा। दुबई की अपेक्षा शारजाह एयरपोर्ट पर उडानों का संचालन कम होने से यात्रियों को चेकइन और चेकआउट में परेशानी नहीं होगी।

बरसात के मौसम में जामुन खाने से सेहत को मिलते हैं अनेक फायदे

बूस्ट होगी इम्यूनिटी

मानसून के सीजन में जामुन खूब खाया जाता है। इसी मौसम में जामुन बेहद टेस्टी लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं? जामुन खाने से सेहत को मिलते हैं जबरदस्त फायदे। बरसात के मौसम में जामुन खाना किसी वरदान से कम नहीं हैं।

जामुन सेहत के लिए बेहद लाभकारी होता है। इसे बरसात के मौसम में खाना सबसे बढ़िया माना जाता है। बारिश के मौसम में जामुन का सेवन काफी हेल्दी माना जाता है। जामुन खाने से बड़े से बड़े रोगों से छुटकारा मिल जाता है। डायबिटीज रोगियों के लिए जामुन किसी वरदान से कम नहीं है। जामुन में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। जामुन में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होती है। इस मौसम जामुन खाना सेहत के लिए बढ़िया होता है। आइए जानते हैं इसके फायदे।

ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है

जामुन सेहत के लिहाज काफी फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा पाई जाती है। जामुन में जम्बोलिन नामक कंपाउंड पाया जाता है। इसके सेवन से ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। जामुन में मिलने वाले जंबोसिन और जंबोलिन नामक यौगिक ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।

पाचन में सुधार होता है

जामुन खाने से पेट संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। इस फल में सबसे ज्यादा फाइबर होता है, जो पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाता है और कब्ज को दूर करता है। इसलिए इस मौसम में जामुन का सेवन जरुर करें।

इम्यूनिटी बूस्ट करना

जामुन खाने से कई चमत्कारिक फायदे मिलते हैं। अगर आप जामुन खाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। जामुन में हाई विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसका सेवन करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी।

वजन घटाने में फायदेमंद

जामुन खाने से वजन भी कम किया जा सकता है। इसमें लो कैलोरी और हाई फाइबर होने के कारण वेट लॉस में मददगार है। जामुन आपकी क्रेविंग को कंट्रोल करने और भूख का एहसास भी नहीं होने देते ।

स्किन और हेयर्स के लिए हेल्दी

रोजाना आप जामुन का जूस या घर पर जामुन शॉट्स बनाकर इसका सेवन करेंगे, तो स्किन एकदम शाइन करेगी और हेयर्स मजबूत बनेंगे। इस बरसात के मौसम में आप भी जामुन खाएं और स्किन को चमकदार बनाएं।

बुढ़ापे तक हेल्दी रहने के लिए फॉलो करें ये रूल्स

हेल्दी और फिट रहने के लिए हम आपको एक्सपर्ट के बताए तीन ऐसे रूल्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको फॉलो करने से आप डिजीज फ्री रहेंगे। तो आइए जानते हैं इन तीन रूल्स के बारे में। अक्सर लोगों को छोटी-मोटी बीमारियां जैसे सर्दी-जुकाम लगा रहता हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको बुढ़ापे तक बीमारियां न हों और किसी लंबे इलाज की जरूरत न पड़े, तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करना चाहिए। बता दें कि हेल्दी और फिट रहने के लिए हम आपको एक्सपर्ट के बताए तीन ऐसे रूल्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको फॉलो करने से आप डिजीज फ्री रहेंगे।

फॉलो करें ये रूल्स

हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, हेल्दी रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप भूख से थोड़ा कम खाना खाएं। क्योंकि कम खाना खाने से आप बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर आप अधिक खाना खाते हैं, तो आप डायबिटीज, मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आज कम समय में हम सभी अनहेल्दी फूड्स का सेवन अधिक करते हैं, लेकिन जब आप कम खाएंगे तो आपको फायदा होगा। मानसून में बीमारियां काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में अच्छी सहेत के लिए मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होना काफी जरूरी है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। क्योंकि जब आप सकारात्मक तरीके से सोचते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी बेहतर तरीके से काम करती है और आप बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ सकती हैं। वहीं सकारात्मक तरीके से सोचने से उच्च रक्तचाप नहीं होता है।

इसके साथ ही फिट रहने के लिए अपने रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी को शामिल करें। जरूरी नहीं है कि आप जिम में जाकर एक्सरसाइज करें, बल्कि आप घर पर योग या फिर ठंडी हवा में वॉक कर सकते हैं। रोजाना कम से कम 30 मिनट जरूर टहलना चाहिए। क्योंकि रोजाना टहलने से ब्रेन, हार्ट समेत ओवरऑल हेल्थ को फायदा पहुंचता है।

सदियों से चली आ रही है खाटू श्याम को निशान अर्पित करने की परंपरा

सनातन धर्म में ध्वज को विजय का प्रतीक माना जाता है। वहीं खाटू श्याम को निशान अर्पित करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसे में आज भी यह परंपरा निभाई जा रही है। निशान को ध्वज और झंडा कहा जाता है।

राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर देशभर में फेमस है। बता दें कि इस मंदिर में श्रीकृष्ण के साथ पांडव भीम के पोते घटोत्कच्छ के बेटे की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। रोजाना हजारों-लाखों की संख्या में भक्त खाटू श्याम के दर्शन के लिए सीकर पहुंचते हैं। जो भी भक्त बाबा श्याम के दर्शन के लिए जाते हैं, उनमें से ज्यादातर भक्त अपने साथ खाटू श्याम का ध्वज लेकर जाते हैं। इस ध्वज को निशान कहा जाता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि भक्त बाबा खाटू श्याम को निशान क्यों अर्पित करते हैं।

जानिए क्या है वजह

सनातन धर्म में ध्वज को विजय का प्रतीक माना जाता है। वहीं खाटू श्याम को निशान अर्पित करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसे में आज भी यह परंपरा निभाई जा रही है। निशान को ध्वज और झंडा कहा जाता है। इस निशान को खाटू श्याम द्वारा दिए गए बलिदान और दान का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि खाटू श्याम ने श्रीकृष्ण के कहने पर धर्म की जीत के लिए अपना शीश समर्पित कर दिया था। ऐसे में युद्ध की जीत का पूरा श्रेय श्रीकृष्ण को दिया था।

कैसा होता है ये निशान

बता दें खाटू श्याम को जो निशान अर्पित किया जाता है, वह नारंगी, लाल और केसरिया रंग का होता है। इसके अलावा इसमें श्रीकृष्ण, खाटू श्याम की फोटो और मोर पंख होता है। मान्यता के मुताबाकि जो भी भक्त खाटू श्याम पर इस निशान को अर्पित करता है,

उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। वहीं कुछ लोग मनोकामना पूरी होने पर खाटू श्याम को निशान अर्पित करते हैं।

कौन हैं खाटू श्याम

बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। वह भीम के पोते और घटोत्कच्छ के पुत्र हैं। उनका संबंध महाभारत काल से है। बर्बरीक बेहद ताकतवर थे, ऐसे में श्रीकृष्ण ने उनसे प्रभावित होकर उनके कलियुग में अपने नाम से पूजे जाने का आशीष दिया था।

ऑफिस में खुद को तरोताजा और आकर्षक बनाए रखने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

अगर आप भी कार्यस्थल पर अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं? एक बेहतरीन त्वचा देखभाल दिनचर्या मदद कर सकती है! आपकी त्वचा को चमकदार बनाए रखने और काम में आपको सर्वश्रेष्ठ महसूस कराने के लिए यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं।

कार्यस्थल पर आत्मविश्वास सिर्फ सही कपड़े पहनने या प्रेजेंटेशन तकनीकों में महारत हासिल करने से कहीं अधिक आप पर निर्भर करता है। अगर आप आपकी खुद की त्वचा को आरामदायक और आत्मविश्वास महसूस करने के बारे में जरुर सोचना चाहिए। पेशेवर क्षेत्र में, आत्मविश्वास प्रदर्शित करना महत्वपूर्ण है। जबकि आपकी विशेषज्ञता और कौशल आपके करियर की सफलता की रीढ़ हैं, एक शानदार और अच्छी तरह से तैयार उपस्थिति बनाए रखने से आपकी पेशेवर छवि को काफी बढ़ावा मिल सकता है। एक प्रभावी त्वचा देखभाल दिनचर्या उस संयमित और आत्मविश्वासपूर्ण लुक को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण घटक है।

ठोस दिनचर्या से शुरुआत करें

क्लींजर का प्रयोगः अपनी त्वचा की प्राकृतिक नमी को छीने बिना गंदगी, तेल और अशुद्धियों को हटाने के लिए एक सौम्य क्लींजर का उपयोग करें। प्रतिदिन सुबह और शाम दो बार सफाई करें।

टोनिंगः टोनर आपकी त्वचा के पीएच को संतुलित करने और इसे आपकी दिनचर्या के अगले स्टेप के लिए तैयार करने में मदद कर सकता है। अपनी त्वचा को शुष्क होने से बचाने के लिए अल्कोहल-मुक्त टोनर चुनें।

मॉइस्चराइजिंगः हाइड्रेशन सभी प्रकार की त्वचा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा मॉइस्चराइज़र चुनें जो आपकी त्वचा के प्रकार के अनुरूप हो - तैलीय त्वचा के लिए हल्के जैल और ड्राई त्वचा के लिए समृद्ध क्रीम।

धूप से सुरक्षाः सनस्क्रीन से समझौता नहीं किया जा सकता। यूवी क्षति से बचाने के लिए, घर के अंदर भी, हर दिन ब्रॉड-स्पेक्ट्रम एसपीएफ30 या उच्चतर का उपयोग करें।

हाइड्रेशन जरुरी

निर्जलित त्वचा सुस्त और थकी हुई दिख सकती है। दिन भर में भरपूर पानी पीना महत्वपूर्ण है, लेकिन हाइड्रेटिंग त्वचा देखभाल उत्पादों का उपयोग करने से अतिरिक्त बढ़ावा मिल सकता है। नमी बनाए रखने और अपनी त्वचा को कोमल और चमकदार बनाए रखने के लिए हयालूरोनिक एसिड, ग्लिसरीन और सेरामाइड्स जैसे इंग्रेडिएंटकी तलाश करें। लंबे समय तक चलने वाले परिणामों के लिए, प्रोफिलो के साथ बायो-रीमॉडलिंग जैसे उपचारों पर विचार करें, जो चेहरे, गर्दन और हाथों को गहराई से हाइड्रेट करने और लोच में सुधार करने के लिए अल्ट्राप्योर हयालूरोनिक एसिड का उपयोग करता है।

आंखों की देखभाल

आपकी आंखों के आसपास की नाजुक त्वचा अक्सर थकान और उम्र बढ़ने के लक्षण दिखाने वाला पहला क्षेत्र है। काले घेरे, सूजन और बारीक रेखाओं जैसी समस्याओं से निपटने के लिए आई क्रीम का उपयोग करें। कैफीन, विटामिन सी और पेप्टाइड्स जैसे तत्व आंखों के नीचे के क्षेत्र को चमकदार और मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं।

नियमित एक्सफोलिएट करें

नियमित एक्सफोलिएशन मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है, जिससे त्वचा चिकनी और अधिक चमकदार होती है। सप्ताह में 1-2 बार हल्के स्क्रब या अल्फा हाइड्रॉक्सी एसिड (एएचए) या बीटा हाइड्रॉक्सी एसिड (बीएचए) युक्त रासायनिक एक्सफोलिएंट का उपयोग करके एक्सफोलिएट करने का लक्ष्य रखें। यह त्वचा की बनावट में सुधार कर सकता है और अन्य त्वचा देखभाल उत्पादों के अवशोषण को बढ़ा सकता है।

अच्छे से आराम करें

नींद समग्र स्वास्थ्य और त्वचा देखभाल दोनों का एक महत्वपूर्ण घटक है। नींद की कमी से काले घेरे, सूजन और रंग फीका पड़ सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी त्वचा ताजा और तरोताजा दिखे, हर रात 7-9 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद का लक्ष्य रखें। लगातार सोने का शेड्यूल आपकी त्वचा की प्राकृतिक मरम्मत प्रक्रियाओं को विनियमित करने में भी मदद कर सकता है।

तनाव का प्रबंधन करें

तनाव आपकी त्वचा पर बुरा असर डाल सकता है, जिससे मुंहासे और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। तनाव प्रबंधन तकनीकों जैसे व्यायाम, ध्यान, या यहां तक कि हर दिन कुछ मिनट गहरी सांस लेने को शामिल करें। तनाव पर नियंत्रण रखने से रंग साफ, स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

मेकअप, अधिकतम प्रभाव

ऐसे सेट-अप में प्राकृतिक, पॉलिश किया हुआ लुक अक्सर सबसे उपयुक्त होता है। ऐसे मेकअप का चयन करें जो बहुत ज़्यादा मेकअप किए बिना आपकी विशेषताओं को निखारे। एक हल्का फाउंडेशन या बीबी क्रीम, मस्कारा का एक स्पर्श और एक न्यूट्रल लिप कलर आपको एक साथ और पेशेवर दिखने में मदद कर सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह पूरे कार्यदिवस तक बना रहे, अपने मेकअप को सेटिंग स्प्रे या पाउडर से सेट करना न भूलें।

मांडविया ने मनु भाकर से की मुलाकात, बोले- करोड़ों युवाओं को प्रेरित करेंगी

मनु ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता और फिर सरबजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में भी कांस्य पदक हासिल किया। मनु ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बनीं थीं।

केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पेरिस ओलंपिक में दो कांस्य पदक जीतने वाली महिला निशानेबाज मनु भाकर और उनके कोच जसपाल राणा के साथ मुलाकात की। मांडविया ने इस दौरान कहा कि मनु की उपलब्धि युवाओं की एक पूरी पीढ़ी को इस खेल को अपनाने और गौरव हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी। 22 वर्षीय मनु एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहल खिलाड़ी बनी थीं।

मनु ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता और फिर सरबजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में भी कांस्य पदक हासिल किया। मनु ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बनीं थीं। मनु ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने के बाद बुधवार को भारत लौटीं जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। सैकड़ों समर्थक लगातार हो रही बारिश के बावजूद नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने के लिए मौजूद थे। वह रविवार को होने वाले पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भाग लेने के लिए शनिवार को पेरिस वापस जाएंगी जहां वह भारत की ध्वजवाहक में से एक होंगी।

मनु से मिले खेल मंत्री

खेल मंत्री ने मनु, उनके पिता राम किशन और निजी कोच जसपाल राणा के साथ बातचीत की तस्वीरें साझा कीं और सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, पेरिस ओलंपिक 2024 में दो कांस्य पदक जीत कर स्वदेश लौटीं देश की बेटी मनु भाकर से आज मिलकर उन्हें इस ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई व शुभकामनाएं दीं। मनु भाकर की यह सफलता भारतीय खेल जगत के करोड़ों युवाओं को प्रेरित करेगी। पूरे देश को उन पर गर्व है। मनु ने कहा था कि उनकी निगाहें अभी से 2028 में होने वाले लॉस एंजिलिस ओलंपिक पर टिकी हुई हैं और वह भविष्य में लगातार अच्छे नतीजे देने के लिए कड़ी मेहनत करती रहेंगी। मनु ने कहा था, एक ओलंपिक के खत्म होने के बाद अब मेरे दिमाग में अगला ओलंपिक चल रहा है और इसके लिए सफर शुरू हो चुका है। अब पेरिस के बाद लॉस एंजिलिस ओलंपिक की यात्रा शुरू हो चुकी है और थोड़े ब्रेक के बाद मैं इसकी तैयारी शुरू कर दूंगी।

जल्द होगा फैसला

ICC : भारत में हो सकता है महिला टी20 वर्ल्ड कप

अगर बांग्लादेश टूर्नामेंट की मेजबानी ले ली जाती है तो इसमें कुछ भी हैरान करने वाला नहीं होगा। देश में लंबे समय से कर्फ्यू है, इंटरनेट बंद होने के साथ-साथ दंगे, आगजनी और हिंसा हो रही है। आईसीसी एक सप्ताह में फैसला ले सकता है। अन्य विकल्पों में भारत एक मजबूत दावेदार है।

विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में होना था, लेकिन बांग्लादेश में हुए हालिया घटनाक्रमों ने आईसीसी को असमंजस में डाल दिया है। देश में आंतरिक अशांति ने अक्टूबर में होने वाले वैश्विक आयोजन की सुरक्षा को लेकर आईसीसी मुख्यालय दुबई में चिंता बढ़ा दी है। वहीं क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार अगर बांग्लादेश टूर्नामेंट की मेजबानी ले ली जाती है तो इसमें कुछ भी हैरान करने वाला नहीं होगा। देश में लंबे समय से कर्फ्यू है, इंटरनेट बंद होने के साथ-साथ दंगे, आगजनी और हिंसा हो रही है। आईसीसी एक सप्ताह में फैसला ले सकता है। अन्य विकल्पों में भारत एक मजबूत दावेदार है।

शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद छोड़ने और देश छोड़ने के बाद आईसीसी के प्रवक्ता ने कहा कि, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उनकी सुरक्षा एजेंसियों और अपने स्वतंत्र सुरक्षा सलाहकारों के साथ समन्वय में आईसीसी घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रहा है। हमारी प्राथमिकता सभी प्रतिभागियों की सुरक्षा और भलाई है।

साथ ही दस टीमों को 3 से 20 अक्टूबर तक बांग्लादेश के ढाका में शेरे बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम और सिलहट में सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 18 दिनों में 23 मैच खेलने हैं। लेकिन मौजूदा हालात को देखकर टूर्नामेंट का आयोजन मुश्किल लग रहा है। आईसीसी टूर्नामेंट के लिए बांग्लादेश के टाइम जोन वाला देश चुन सकता है। भारत के अलावा यूएई और श्रीलंका भी इस आवश्यकता को पूरा करते हैं।

तुषार का छलका दर्द, कहा-

फिल्मी परिवार से होने का फायदा सब बताते हैं नुकसान नहीं...

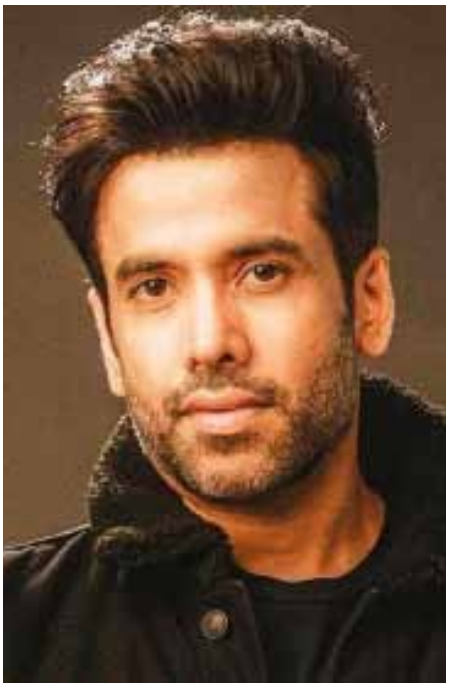

बॉलीवुड अभिनेता तुषार कपूर ने हाल में ही ओटीटी पर डेब्यू किया है। उन्होंने वेब सीरीज 'दस जून की रात' के साथ अपनी नई पारी की शुरुआत की है। तुषार मशहूर फिल्मी परिवार से आते हैं। वह दिग्गज अभिनेता जितेंद्र के बेटे हैं और मशहूर प्रोड्यूसर एकता कपूर के भाई हैं। फिल्मी पृष्ठभूमि से होने के बावजूद उन्हें कई बार खारिज किया जा चुका है। हाल में ही अभिनेता ने इसे लेकर बात की है।

अभिनेता ने बताया कि लोग फिल्मी परिवार से होने के फायदे के बारे में बात करते हैं, लेकिन नुकसान को लेकर नहीं। हाल में ही इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू के दौरान अभिनेता ने अपने फिल्मी करियर को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि वो खुद को साबित करने का अवसर पाकर धन्य महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि वो उन अभिनेताओं में से एक हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा बार खारिज किया गया है। उन्होंने आगे कहा, 'लोग फिल्मी परिवार से आने के फायदों के बारे में तो बात करते रहते हैं, मेरे पास भी सब कुछ था। हालांकि, मुझे कई नुकसानों और लगातार हर बार खुद को साबित करने के लिए जूझना पड़ा। हर बार किसी नए छात्र की तरह मुझे बार-बार परीक्षाएं देनी पड़ीं।" अभिनेता ने इस दौरान खुद को भाग्यशाली बताते हुए कहा कि बार-बार खारिज किए जाने के बाद भी उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के कई अवसर मिले।

तुषार कपूर ने आगे कहा कि उनकी पहली फिल्म 'मुझे कुछ कहना है' एक सफल फिल्म रही थी, लेकिन लोगों को उन्हें लेकर संदेह बना हुआ था। इसके बाद फिल्मों की असफलता ने उनके अभिनय क्षमता पर लोगों का संदेह और बढ़ा दिया। इस दौरान उन्हें इंडस्ट्री के कई लोगों की नकारात्मकता का सामना भी करना पड़ा। हालांकि, 'क्या कूल है हम' ने कॉमेडी में उनकी पहचान स्थापित करने में उनकी मदद की।

'स्त्री 2' के बाद नागिन की भूमिका में नजर आएंगी श्रद्धा, टाइम ट्रेवल पर आधारित फिल्म..

सबसे पहले बात करते हैं श्रद्धा की आगामी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'स्त्री 2' की। इस फिल्म में श्रद्धा के अलावा राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी और अपारशक्ति खुराना मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। 'स्त्री 2' अमर कौशिक द्वारा निर्देशित और मैडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियो के बैनर तले दिनेश विजन और ज्योति देशपांडे द्वारा निर्मित है। यह एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है। बता दें यह फिल्म 2018 में आई 'स्त्री' की अगली कड़ी है। यह मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स की पांचवीं किस्त है। फिल्म 15 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। 'स्त्री 2' के बाद श्रद्धा की फिल्म 'स्त्री 3' भी आएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 'स्त्री 2' के प्रमोशन के दौरान ही 'स्त्री 3' बनाने की घोषणा की जा चुकी है। हालांकि अभी तक समय और साल निर्धारित नहीं किया गया है कि 'स्त्री 3' कब आएगी। लेकिन प्रशंसकों में 'स्त्री' और फिर 'स्त्री 2' की उत्सुकता को देखते हुए फिल्म निर्माताओं ने इस फिल्म की तीसरी किस्त लाने का फैसला किया है।

अब बात करते हैं श्रद्धा कपूर की एक और आने वाली फिल्म की, जो टाइम ट्रेवल पर आधारित है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, श्रद्धा एक टाइम ट्रेवल पर आधारित फिल्म में नजर आएंगी। बहरहाल, फिल्म का नाम अभी तक तय नहीं हुआ है और ना ही फिल्म की बाकी स्टारकास्ट के बारे में कोई जानकारी सामने आई है, लेकिन इतना जरूर तय है कि इस फिल्म में श्रद्धा कपूर जरूर नजर आएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 'नागिन' नाम की फिल्म या फिर फिल्म में नागिन के किरदार में श्रद्धा दिखाई देंगी। यह किरदार पहले दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी ने निभाया था। हालांकि श्रद्धा कपूर के लिए यह रोल आसान होने वाला नहीं है। लेकिन, श्रद्धा को इस रोल में देखना वाकई दिलचस्प होगा। बता दें फिल्म के प्रोड्यूसर हैं निखिल द्विवेदी और डायरेक्टर विशाल फुरिया।

हमारा देश हमारा अभिमान

हर-हर महादेव

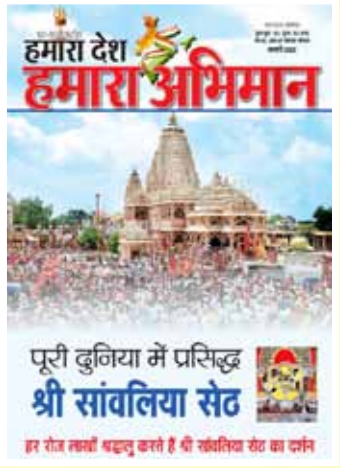

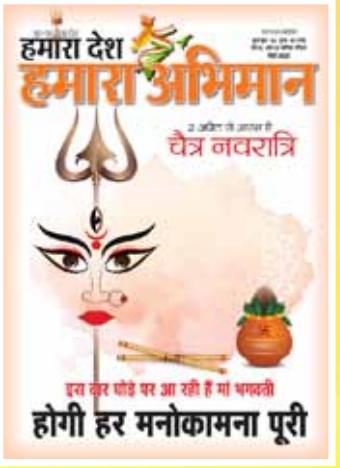

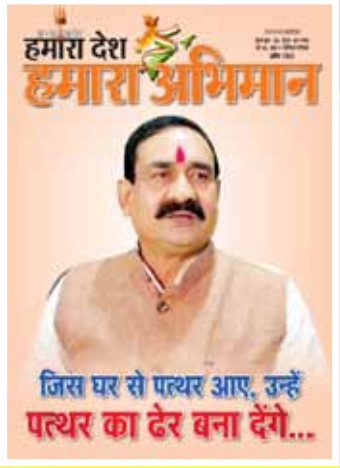

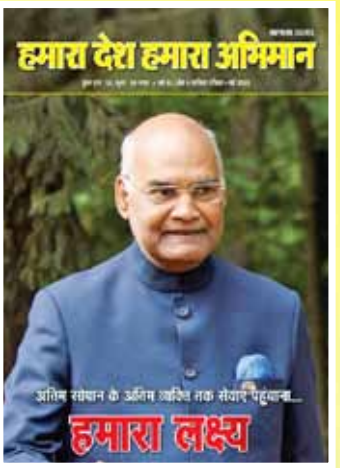

हमारा देश हमारा अभिमान मासिक पत्रिका की प्रति बुक करने के लिए सम्पर्क करें..

मनोज चतुर्वेदी : 98266 36922, 88392 59136

मध्यप्रदेश शासन

देश की आज़ादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को कृतज्ञतापूर्ण नमन

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

78 वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

चौतरफा विकास का परचम लहराता मध्यप्रदेश

युवाओं के लिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं व्यावसायिक क्षमता निर्माण के लिए सभी 55 जिलों में पी.एम. कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस प्रारंभ

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर प्रदेश में पहली बार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहे आयोजित

संबल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आहार अनुदान योजना एवं राशन आपके ग्राम जैसी योजनाओं के माध्यम से गरीब और जरूरतमंदों को सहायता

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में 1.29 करोड़ महिलाओं को रक्षाबंधन पर प्रतिमाह ₹1250 के अतिरिक्त ₹250 का विशेष उपहार, अब तक ₹22 हजार 924 करोड़ की सहायता, लाड़ली लक्ष्मी योजना के माध्यम से बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 83 लाख से अधिक किसानों को ₹14254 करोड़ की सहायता

डॉ. मोहन यादव
मुख्यमंत्री

@Cmmadhyapradesh
@jansampark.madhyapradesh
@Cmmadhyapradesh
@jansamparkMP
jansamparkMP

मध्यप्रदेश शासन

D18008/24